

Daily

सच के हक में...

THE PHOTON NEWS

द फोटोन न्यूज

Published from Ranchi



अन्त की यात्रा

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

आर्थिक पुनर्जागरण का महानायक पंचतत्व में विलीन

AGENCY NEW DELHI :

शनिवार को देश में आर्थिक पुनर्जागरण के सूत्रधार, विकास के नए द्वार खोलने वाले सुधारों के जनक और राजनीति में सादगी तथा सौम्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिंह की तीन बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने उनकी चिता को मुख्याग्नि दी। देश तथा दुनिया के कई गणमान्य लोगों, राजनीतिज्ञों और आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में

तीनों सेनाओं ने 21 तोपों से दी सलामी, बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने दी मुख्याग्नि, अन्य दो बेटियां और पत्नी रहीं मौजूद



नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य हस्तियों ने

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने किया नमन



9:30 के बाद कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई अंतिम यात्रा

डॉ. मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को सुबह 9:30 बजे उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। इसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे थे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुदुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। वे लंबे समय से बीमार थे।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, सोनिया राहुल और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि



पहनाई गई नीली पगड़ी

अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। कांग्रेस मुख्यालय से पार्थिव शरीर को रेलगाड़ी की टोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। पूर्व प्रधानमंत्री का सिख धर्म के अनुष्ठानों और उद्घोष के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की।

मनमोहन के स्मारक पर छिड़ा विवाद

निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कैसी वेणुगोपाल ने कहा- सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई। वे देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को

मोदी-शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहाँ अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।

चिट्ठी लिखकर डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया, जहाँ स्मारक बन सके। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉ. सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी यही चाहती थीं। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा, अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा।

जिम्मे खेरस नामग्याल वांगचुक और मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भी निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

SARAFI

सोना : 6,795

चांदी : 98.05

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

जो कहा, उसे रिकॉर्ड समय में किया पूरा : हेमंत सोरेन

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मईया समान योजना को लेकर

कहा कि जो बोला, उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में

आगे लिखा है कि

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण मईया समान का कार्यक्रम टाल दिया गया है, पर

मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनता से किया था, उसे पूरा कर रहा हूँ। हर मईया के खाते में हर माह

2500 रुपये दिए जा रहे हैं। साल में पूरे 30,000 रुपये मिलेंगे।

नौकरशाही



ब्रजेश मिश्रा

दावा है कि बड़ी कुर्सियों पर बैठे दो हुकूमतारों के बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

...तो डील पक्की समझें

शरीर बढ़ का एक बड़ा चर्चित शेर है- कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यू ही कोई बेवफा नहीं होता। झारखंड की नौकरशाही के गलियारे में इन दिनों एक ऐसी ही बेवफाई के किस्से फिजाओं में तेर रहे हैं। मामला सोमरस वाले महकमे से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा है कि बड़ी कुर्सियों पर बैठे दो हुकूमतारों के बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। अरे हाँ, वही, जिस मोजुदा कल्चर में डील कहते हैं। हम इसे 'इश्क' मान लेते हैं। बहरहाल, बात यह तय हुई कि प्रतिदिन सुरा बिक्की से होने वाले कलेक्शन के अनुसार एक निश्चित हिस्सा छोट्टे हाकिम बड़े हाकिम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

रहे। जैसा कि मुहब्बत में अवसर होता है, मिलन के बाद जुदाई, संयोग के बाद वियोग। आखिरकार, यहाँ भी वह घड़ी आ गई। एक दिन छोट्टे साहब ने बड़े साहब से अपने दिल की बात कह दी। बताया कि अब वह इस रिश्ते को और कायम नहीं रख सकेगा। अगले कुछ महीनों में उन्हें अपना आशियाना छोड़कर जाना है। लिहाजा समझौते के तहत प्यार की निशानी के तौर पर भेजे जाने वाले 'गुलदस्ते' अब नहीं जा सकेगा। बस फिर क्या था, यहाँ भी 'दुकरा के मेरा प्यार' टाइप मामला बन गया। इस बेवफाई से बड़े साहब के दिल पर इतनी गहरी चोट लगी कि उन्होंने छापेमारी शुरू करा दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म 'हॉटस्टार' की मोजुदा टॉप वेब सीरीज से लेकर राजकुमार राव की फिल्म 'शादी में जरूर आना' तक में तो इतकाम लेने



का यही तरीका बताया गया है। खेर, बड़े साहब की इस नाराजगी से छोट्टे साहब के पूरे प्लान पर संकट के बादल छाते लगे। ठंड के इस मौसम में कहीं बारिश न हो जाए, लिहाजा छोट्टे साहब ने फिर समझौते की पहल की। बड़े साहब के दरबार में पहुँचे, दोहराया कि अब विदा होने

की बेला आ रही है। कुछ तो पुराने रिश्ते का ख्याल कोजिए। अब पहले जैसे 'गुलदस्ते' नहीं भेज पाएंगे। कुछ फूल अपने साथ ले जाने हैं, सौ, संबंध कायम रखने के लिए अब से बस कुछ गुलाब ही दिखेंगे। अब कारिंदे पूछ रहे हैं- तो डील पक्की समझें।



आज नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाएंगे पीएम गाजियाबाद दौरा स्थगित

NEW DELHI : रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद दौरा स्थगित हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है।

प्रधानमंत्री को 29 दिसंबर को साहिबबाद से न्यू अशोक नगर (दिल्ली) के बीच नमो भारत ट्रेन के परियोजना को हरी झंडी देने आने वाले थे। पिछले तीन दिन से गाजियाबाद जिला प्रशासन, पुलिस और एनसीआरटीसी के तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए थे। एसपीजी के कार्यक्रम के लिए अतिथि के साथ आरआरटीएस स्टेशन के साथ ही प्रधानमंत्री के पूरे प्रस्तावित रुट का आयोजन किया था।

अधिकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री को वायु मार्ग से हिंडन पहुंचना था और उसके बाद सड़क मार्ग से साहिबबाद आरआरटीएस स्टेशन पर सेरेमनी के साथ नमो भारत से ही दिल्ली जाने का कार्यक्रम था।

गिरिडीह में नक्सलियों के मददगारों के घर अचानक पहुंची एनआई की टीम



PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआई) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम अचानक गिरिडीह पहुंची। यहाँ नक्सली कृष्णा हांसदा से जुड़े मामले को लेकर कई घरों में छापेमारी की।

जिन घरों में टीम ने छापेमारी की है, वे घर नक्सलियों के लिए काम करने वाले सदिग्ध और ओवर ग्राउंड वर्कर्स के हैं। लगभग पूरे दिन चली कार्रवाई में टीम ने न केवल घरों की तलाशी ली, बल्कि उनसे जुड़े दूसरे परिसरों की भी जांच की। जांच के दौरान कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि जब्त किए गए। बताया जाता है कि एनआई की टीम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन, पीरटांड समेत अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी के

नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन, पीरटांड समेत अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी

नक्सली कृष्णा हांसदा से जुड़े मामले में कई टिकानों पर रेड, मोबाइल सहित कई सामान जब्त

बाद एक और जहाँ इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तार नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर एनआई की टीम नक्सलियों के रामदयाल महतो के घर से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया है।

15 लाख का इनामी नक्सली है कृष्णा

छापेमारी करने पहुंची टीम को लेकर इलाके में भारी सख्ती में बल के जवान तैनात किए गए थे। इस मामले को लेकर कोई भी पुलिस पदाधिकारी एनआई की टीम से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया। दरअसल टीम ने जिस मामले में जांच की है, वह आरसी-01/2023/एनआई-आरएनसी का है। यह केस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के नक्सली कैडर कृष्णा

हांसदा की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्रीय समिति सदस्य नक्सली कैडर कृष्णा हांसदा को जनवरी 2023 में दुमरी थाने के सुनियोजित वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। एनआई की जांच के दायरे में ऐसे लोग थे जो गिरिडीह जिले के पारसनाथ क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) को खाने-पीने की वीजें और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उपलब्ध कराते थे।

बेहतर सेहत भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किए चार महत्वपूर्ण यौगिक

डायबिटीज के इलाज में कारगर भूमिका निभाएगा सुबबूल

AGENCY NEW DELHI :

आज के समय में आदमी का जीवन कई स्तरों पर विभिन्न तनावों से गुजर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कम उम्र में डायबिटीज और हार्ट संबंधी बीमारियाँ पैदा हो जा रही हैं। मेडिकल साइंस में डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं। इसमें टाइप 2 को अधिक गंभीर माना जाता है। हाल के एक महत्वपूर्ण अध्ययन में मधुमेह के टाइप 2 के इलाज में सुबबूल (ल्यूकेना) नामक चिकित्सकीय पौधा की कारगर भूमिका की जानकारी दी गई है। रिसर्च में प्राप्त तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि टाइप-2 मधुमेह के इलाज में औषधीय पौधा सुबबूल का बीज बेहद कारगर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ही इसकी खोज की है और इससे चार सक्रिय यौगिक विकसित किए हैं। जन्तल एसीएस और मेगा में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, मधुमेह और संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए यह पौधा बेहद उपयोगी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान गुवाहाटी के आईएएसएस्टी के शोधकर्ताओं के मुताबिक, सुबबूल के बीज और फलियों में इसलिन प्रतिरोध को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।

मधुमेह और संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए अत्यंत उपयोगी है यह पौधा आईएएसएस्टी के शोधकर्ताओं ने इसके बीजों और फलियों पर किया है शोध



मुंह की बीमारियों के इलाज में भी सक्षम

मुंह की बीमारियों के इलाज में भी सक्षम विशेषज्ञों के अनुसार, सुबबूल सांसें से आने वाली बदबू और मुँह से जुड़ी बीमारियों के लिए भी कारगर है। यह दांतों के स्वास्थ को बढ़ावा देता है। यह दांतों के छिलके और फली का उपयोग दांत दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। पेट की कोमल शाखाओं का उपयोग दांतुन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह विभिन्न दंत संक्रमणों को ठीक करता है। इसकी छाल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से त्वचा की सूजन, जलन और लालिमा कम होती है।

प्रोटीन-फाइबर का स्रोत

सुबबूल या ल्यूकेना एक तेजी से बढ़ने वाला फलदार पेड़ है। अमरतर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। पत्तियों और बीजों को सूप या सलाद के रूप में कच्चा और पकाकर खाया जाता है। यह प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। इसके कारण विभिन्न जातीय समुदाय इसका पारंपरिक उपयोग करते हैं। यह कम पानी और कम देखरेख पर भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका उपयोग इंधन एवं बायोमास के लिए किया जा सकता है।



स्मृतियों में बसी अमरावती व रुक्मिणी मंदिर

भा गदौड़ भरी मुंबई की जिनगी से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर कहीं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि कुछ दोस्तों ने कहा इस बार अमरावती चलते हैं और दो दिन बाद हम रवाना हुए। यह महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर प्राचीन देवी अंबादेवी मंदिर और संत गाडगे महाराज की कर्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अमरावती प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें चिखलदरा हिल स्टेशन और मेलघाट टाइगर रिजर्व जैसे स्थान शामिल हैं। यह शहर विदर्भ क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी है और यहाँ की स्थानीय कला और हस्तशिल्प इसे और विशेष बनाते हैं। मेरी यह यात्रा अमरावती के अनखुए पहलुओं को जानने और अनुभव करने का एक अद्भुत अवसर बनी।

युगवक्ता की पाती

मुंबई से अमरावती की दूरी लगभग 670 किलोमीटर है। मैंने सुबह 6 बजे मुंबई से ट्रेन पकड़ी, जो 12 घंटे में मुझे अमरावती पहुँचाती है। सफर के दौरान विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के दृश्य ने यात्रा को आनंदमय बना दिया। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ मध्य भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल हिस्सा हैं। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ते हुए एक प्राकृतिक विभाजन रेखा का कार्य करते हैं। इसकी हरियाली से भरी पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और अद्भुत झरने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के जंगलों में बाघ, तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं।

मुंबई से अमरावती की दूरी लगभग 670 किलोमीटर है। मैंने सुबह 6 बजे मुंबई से ट्रेन पकड़ी, जो 12 घंटे में मुझे अमरावती पहुँचाती है। सफर के दौरान विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के दृश्य ने यात्रा को आनंदमय बना दिया। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ मध्य भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल हिस्सा हैं। विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ते हुए एक प्राकृतिक विभाजन रेखा का कार्य करते हैं। इसकी हरियाली से भरी पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और अद्भुत झरने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के जंगलों में बाघ, तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं।



छत्रपति शिवाजी उद्यान

आखिरी में हम छत्रपति शिवाजी उद्यान गए। यह अमरावती जिले का एक प्रमुख आकर्षण और शहर के बीचों-बीच स्थित सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यान है। यह उद्यान अपने हरे-भरे लॉन, मनमोहक फूलों की बगीचों, और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए यह जगह सुबह की सैर, योग और ध्यान के लिए आदर्श स्थान है। बच्चों के लिए यहाँ झूलों और खेल-कूद की व्यवस्था है, जो इसे परिवारों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल बनाता है। उद्यान के अंदर फैली पक्की पगडंडियाँ और आरामदायक बेंच आगंतुकों को शांति से समय बिताने का मौका देती हैं। इस उद्यान का नाम मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में रखा गया है। यह न केवल एक मनोरंजन स्थल है बल्कि अमरावती की हरित धरोहर का प्रतीक भी है। यहाँ समय बिताने का शहर के शौरांगुल से दूर प्रकृति के करीब महसूस करते हैं।

संत गाडगे की कर्मभूमि

अंबादेवी मंदिर शहर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करने से पहले यहाँ पूजा की थी। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियों ने मन को शांत किया। यहाँ हर रोज भजन-कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन होता है। सप्तश्रुंगी मंदिर अमरावती से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सप्तश्रुंगी देवी को नवदुर्गा का एक रूप माना जाता है। पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ का प्राकृतिक

वातावरण और आध्यात्मिक शांति मन को मोह लेती है। अमरावती संत गाडगे महाराज की कर्मभूमि है। उनका स्मारक एक प्रेरणादायक स्थल है, जहाँ उनकी समाजसेवा और शिक्षाओं को याद किया जाता है। दोपहर का भोजन मैंने शिवना दाबा में किया जो अपने पारंपरिक महाराष्ट्रिय भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पीठला-भाकर और कोकम शरबत ने दिन को और खास बना दिया। अमरावती न केवल धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक स्थल और कला केंद्र भी अद्वितीय हैं।

चिखलदरा हिल स्टेशन देगी ताजगी

चिखलदरा हिल स्टेशन देगी ताजगी चिखलदरा हिल स्टेशन अमरावती से 85 किलोमीटर दूर स्थित एकमात्र हिल स्टेशन है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में 1,188 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु, और हरे-भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है।

चिखलदरा का नाम महाभारत के भीम द्वारा कीवक वध की कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित भीमकूट ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ के हरियाली से भरे पहाड़, वायु की ताजगी और शांत वातावरण ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।



संजय शेखर
नई दिल्ली

स्थित राजा देवी मंदिर गया। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और यहाँ का शांत वातावरण यात्रा की थकान मिटाने के लिए बिल्कुल सही था। इसके बाद मैंने पास ही स्थित स्थानीय बाजार में घूमकर स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों की खरीदारी की। रात के लिए मैंने अमरावती के एक बजट फ्रेंडली होटल में चेक-इन किया। यहाँ रहने की कई अच्छी जगहें हैं। अमरावती में होटल ग्रैंड मेहर लक्जरी पसंद लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। सिद्धार्थ होटल भी इस जगह पर है। मध्यम बजट वाले लोग इस जगह पर टहर सकते हैं। बजट ट्रेवलर्स के लिए, इस जगह पर कई तरह के होस्टल भी हैं।

यह शहर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे दिन मैं शहर के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने के लिए निकला। तीन दिनों की यह यात्रा अमरावती की संस्कृति, इतिहास और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर बनी। धार्मिक स्थलों की शांति, प्राकृतिक सुंदरता, और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद अविस्मरणीय था। मुंबई लौटते समय मैंने महसूस किया कि अमरावती न केवल एक यात्रा गंतव्य है, बल्कि यह आत्मा को सुकून देने वाला एक अनुभव भी है। अगर आप भी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक अनुभवों की तलाश में हैं तो अमरावती एक आदर्श

स्थान है। **मेलघाट टाइगर रिजर्व** मेलघाट टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान। यह भारत के शुरूआती नौ टाइगर रिजर्व में से एक है जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। 1,677 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ वन्यजीव प्रेमियों को अद्वितीय अनुभव मिलता है। मेलघाट के घने जंगल, पहाड़ी इलाके, और तेज बहती नदियाँ इसे बाघों, तेंदुओं, गौर, चीतल, सांभर और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का आदर्श आवास बनाते हैं। यहाँ का प्राचीन वातावरण पर्यटकों को प्राकृतिक

सुंदरता और शांति का एहसास कराता है। **कलाप्रेमियों का स्वर्ग वडाली** वडाली तालाब शहर के केंद्र में स्थित है और स्थानीय लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्थल है। तालाब के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना एक अद्भुत अनुभव था। शाम को मैंने अमरावती के कला केंद्र दौरा किया, जहाँ स्थानीय कलाकारों की अद्भुत पेंटिंग्स और शिल्पकला देखने को मिली। यह जगह कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यात्रा के समापन से पहले मैंने कफ ऑफ जो कैफे में कॉफी और पास्ता का स्वाद लिया। यहाँ का माहौल युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है।

कविता

उँ उमा उपाध्याय

पूस की रातें

निगाहों को खटकती हैं मेरी कुछ आज की बातें,
मेरे जज्बात की बातें, यूँही कल आज की बातें-2।
निगाहों को खटकती हैं मेरी कुछ आज की बातें।
ये दिन भर का थका हारा है तन, कपड़े भी हैं कमतर-2
न झबरा ही है बाहों में, ये हल्कू से भी है बदतर,
मुझे अब याद आती हैं वही गोदान की बातें, गरीबों से जरा पूछो, हैं कैसी पूस की रातें-2।
निगाहों को खटकती हैं, मेरी कुछ आज की बातें।
ये गड्या माँ का चूँ राहों में, ठंडी में पड़े रहना, खिला के एक रोटी, कर्म का निर्वाह कर लेना, कि कैसे चैन से बैठेंगे हम, अपनी रसोई में, खटकती हैं कई बातें, मेरे संसार की बातें-2।
निगाहों को खटकती हैं मेरी कुछ आज की बातें
मेरे जज्बात की बातें, मेरे संसार की बातें।

व्यंग्य ■ बर्बरिक

शाह का चमचा

'ब ने है शाह का चमचा, फिर है इतराता वरना आगरे में गालिब की हस्ती क्या है'

मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने जब ये फरमाया था, तब बादशाह की उनपे नुरे नजर थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि मिर्जा गालिब फकीर हो गए। उन्होंने अंग्रेज राजा को अर्जी लगाई कि शाही खजाने से उनको नियामतें अता फरमाई जाएं, तो वो बादशाह के वफादार रहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि राजकाज चलाने के लिये कायदे की और डंडे के जोर की जरूरत होती है। लेकिन शाह बनने का चरका जब लग जाता है तो फिर उसे मेंटेन करने के लिए पीआर एजेंसी की जरूरत पड़ती है। पीआर एजेंसी बताती है कि कौन सा सेलैब्रिटी कितना बोलेगा, कितना ट्वीट करेगा, कब करेगा और किसके शासन को सर्वकालिक श्रेष्ठ शासन घोषित करेगा। कितने पैसे लेकर किसी भी विचारधारा के धरनास्थल पर किस 'गेस्ट अप्रीसेन्स' करनी है। कब डिप्रेसन-डिप्रेसन खेलना है।



दिलीप कुमार

उनको ये सलाह मिली कि किसी पत्रकारिता या लिटरेचर की लाइन में घुस जाओ तो थाना पुलिस का प्रकोप शायद कुछ कम हो। ये बात उनको जँच गयी है, अब वो खुद को काफी सेफ महसूस करते हैं, मीडिया में निवेश करने के बाद। वैसे भी इस देश में मीडिया ट्रायल बड़े जोर-शोर से होता रहता है, जबकि अदालतें कहती रहती हैं कि न्याय करने का काम हमारा है।

लेकिन दुनिया भर में जिसका जो काम नहीं है, वही वो काम करता रहता है, जैसे चीन में एक धर्म विशेष के लोगों को अपने धार्मिक कार्यों को करने की अनुमति नहीं है और पाकिस्तान में कम्युनिज्म पर पाबंदी है। ये दोनों मुल्क भारत को सेक्युलरिज्म न सिर्फ सिखाते हैं, बल्कि उसका उपदेश भी देते हैं। भारत के व्यंग्यकारों को चाहिए कि वे यूनाइटेड नेशन्स को एक पत्र लिखें और इस उलटबासी को 'जोक ऑफ द डिकेड' घोषित करवाएँ। जिस तरह प्रेमचंद साहब कह गए थे कि कोई गम ना हो तो बकरी पाल लो, वैसे ही एक मशहूर व्यंग्यकार का कथन है कि अगर कहीं आपको हँसी ना सूझ रही हो तो वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत कुछ दिलचस्प शब्द बोलता है और मस्त रहने को स्ट्रेस बस्टर बोलता है। पहले लो ग उसे दूधवाला कहकर बुलाते थे, अब वो खुद को इयुनिटी बूस्टर सेलर बताता है।

सिपीयू को जबर लगा कि उनका व्यापार अवैध है तो उन्होंने कुछ कानूनी राय-मशविरा किया, मोटी फीस देकर



जबकि कुछ आर्थिक रिपोर्ट्स के आधार पर भारत, बांग्लादेश से पीछे हो गया है, वहाँ खुशहाली ही खुशहाली हो गयी है तो अब तीन-चार करोड़ अवैध बांग्लादेशी अपने मुल्क लौट जाएँगे। वैसे बुद्धिजीवी वर्ग का एक धड़ा चिंतित भी है कि अगर सारे अवैध बांग्लादेशी चुपचाप बिना किसी धौंगामुश्ती के अपने घर लौट जाएँगे तो उनके हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल जाएगा।

'अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा जो हुक्म हो तो यहाँ छोड़ दूँ फसाने को' हाल ही में दुनिया भर में माफी लेने-देने के लिए मशहूर रही 'एम्नेस्टी इंटरनेशनल' को अचानक खुद माफी की दरकार हो गयी। ब्रिटेन से निकली ये संस्था दुनिया भर के मानवाधिकारों पर सवाल उठाती रहती थी, सिवाय ब्रिटेन के अंदर मानवाधिकार हनन के। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत थी, आखिर कब तक देशों की इज्जत इनकी रैंकिंग से आंकी जाती, सो जब इनकी भी हद हो गयी तो इन्हें एम्नेस्टी की खुद दरकार हो गयी और अंततः भारत से इन्हें जाना ही पड़ा। नाम माफी वाला और हो गए दण्डित। वैसे 2016 में रूस भी इनको देश से दफा कर चुका है। दोस्त, दोस्त के नक्शेकदम पर चला, सो पहले रूस ने, फिर भारत ने एम्नेस्टी को एम्नेस्टी नहीं दी। हैरानी की बात ये है कि कानून के राज की दुहाई देने वाले एम्नेस्टी पर

सरकार ने लगातार भारतीय कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। **'तुलसी कबहुँ न त्यागिये अपने कुल की रीति लायक ही सों कीजिये ब्याह, बैर और प्रीति'** राम के देश में आये थे तो काश इन लोगों ने तुलसीदास को पढ़ लिया होता। ऐसे ही एक और दिलजोई की रिपोर्ट आची है 'हैप्पीनेस इंडेक्स' इस रिपोर्ट में भारत से ज्यादा खुश हैं और पाकिस्तान के वर्ल्ड पावर बनने की ओर अग्रसर है। सही बात है, बगैर बिजली, बगैर शक्कर, बगैर आटा, बगैर पीने का साफ पानी, बगैर इलाज, बगैर सेक्युरिटी वर्ल्ड पावर बनने का एजाज सिर्फ पाकिस्तान के बाशिंदों को ही नसीब है। वाकई पाकिस्तान सुपर पावर है जो बहुत आगे की सोचता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोरोना फैला तो पाकिस्तान ने इलाज करने जैसे तात्कालिक मुद्दों में उलझने के बजाय कब्रें खोदने जैसे दूरगामी निर्णय लिये। तेज गेंदबाज रहे इमरान खान ने तेजी से निर्णय लिया कि हम कोरोना से लड़ नहीं सकते, तो हम अपना वक्त और एनर्जी क्यों बर्बाद करें और वैसे एक अच्छे नेता के तौर पर वो अपने मुल्क के

लोगों को खुशहाल जिंदगी तो दे ना सके तो तसल्लीबख्श मौत का सफर ही आसान कर दें सो हुकूमत के खर्च पर उन्होंने बेइतहा कब्रें खुदवाईं, सही बात है कहीं मिलेंगे ऐसे दूरअंदेश नेता। भारत में तो ओंबामा जब संसद में आकर कह जाते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने की ओर चल नहीं रहा है, बल्कि सुपर पावर बन चुका है, तब भी इसी देश के कुछ लोग भारत को अब भी सुपर पावर मानने को तैयार नहीं हैं। सुई तक न बनाने वाला देश आज दुनिया का फार्मा कैपिटल बन चुका है, लेकिन अल्प बुद्धि वाले बयानवीरों से इस देश को न जाने कब निजात मिलेगी? जैसे राजधानी में एक बयान आया है कि चीनी सेना बारह सौ किलोमीटर अंदर कब्जा कर चुकी है। मैं दिल्ली में था, उत्तर भारत में चीन की सीमाओं से दिल्ली की दूरी का अंदाजा लगाया तो थोड़ी हैरानी हुई। इस हिसाब से तो अब दिल्ली चीन का ही हिस्सा है। चीन के दावे की तस्दीक करने के लिये एक प्लेट चाइनीज का आर्डर दिया मैंने। उसने मुझे कहा 'जय राम जी की' तिरंगे को काउंटर पर प्रणाम करके वो चायनीज बनाने लगा और साथ में गाने भी लगा-

'भारत हमको जान से भी घ्यारा है'। मैं सोच रहा था कि चीन वाली भारत में प्लास्टिक के चावल तो बेचते ही हैं, क्या वो नकली बेबी मिल्क पाउडर भी बेचते लगे हैं या बहुत पहले से भी बेचते रहे हैं?

BRIEF NEWS

सिद्धी की वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश कमेटी का चुनाव आज

RANCHI : रविवार को सिद्धी की वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश कमेटी का चुनाव संत जेवियर स्कूल के पीछे इसलहिया कम्युनिटी हॉल परसटोली में होगा। मतदान सुबह 10 से 3 तीन बजे तक चलेगा। उसके बाद शाम 4 बजे बजे से मतगणना शुरू होगी। परिणाम लगभग शाम 6 बजे हो जाएगा। इसमें झारखंड के सभी जिलों के मतदाता उपस्थित होकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव एवं कोषाध्यक्ष है के पद के लिए अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे। लगभग सभी जिलों से पांच-पांच मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे।

सोमवती अमावस्या 30 को, पूजा से पितृदोष

RANCHI : सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। इस दिन वृद्धि योग और मूल नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है, जो बहुत शुभ माना जाता है। इस संयोग के कारण पिंडदान, तर्पण और महादेव की पूजा से पितृदोष, ग्रह दोष और अन्य कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इस संबंध में पंडित मनोज पांडेय ने शनिवार को बताया कि इस दिन निराहार रहकर-अपने पितरों की मुक्ति की कामना करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा और तर्पण करने का है। उन्होंने कहा कि पितरों की पूजा का महत्व माघ में एक बार आता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिलती है।

झामुमों में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं : चम्पाई

RANCHI : पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन ने झामुमों में वापसी की बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि फिर एक बार, कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत, बार-बार ऐसा कर के समर्थकों में भ्रम पैदा करने और मुझे बदनाम की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि मैं जहां हूँ, भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में, मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं।

दिव्यांगों ने जरूरतमंदों के लिए किया रक्तदान

RANCHI : शनिवार को पहली बार झारखंड प्रशिक्षित विशेष शिक्षक और दिव्यांग संघ रांची ने लहू बोलोगे के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर रांची प्रेस क्लब के बाहर आयोजित किया गया था। जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया, सिक्ल लोम और हीमोफीलिया से ग्रसित लोगों के लिए रक्तदान करना था। शिविर में 6 यूनिट रक्तदान किया गया। 6 यूनिट रक्त रांची सदर अस्पताल के ब्लड बैंक को दिया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने किया। इस अवसर पर लहू बोलोगे संगठन द्वारा डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. अनुराधा वत्स और आयोजक पॉवेल कुमार को सम्मानित किया गया।

अतिक्रमणकारियों पर सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी, होगी कार्रवाई राजधानी में अतिक्रमण खत्म करने के लिए नगर निगम ने कसी कसर

PHOTON NEWS RANCHI :

रांची नगर निगम ने शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक जगहों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर कसर कस ली है। अब निगम के इलाके में अतिक्रमण करना आसान नहीं होगा। अतिक्रमण पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ऐसे में अतिक्रमण करने वालों की पहचान करते हुए उनपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं एक्ट के तहत नियम उल्लंघन करने वालों के सामान भी जब्त कर लिए जाएंगे। बता दें कि शहर में लगाए गए हाई डेफिनेशन वाले कैमरे से पूरे शहर में निगरानी की जा रही है। अभियान के तहत अतिक्रमण या अवैध रूप से

सड़कों को जाम मुक्त बनाने के मार्ग की हर बाधा की जाएगी दूर, नो वेंडिंग जॉन घोषित कर लगाए जा रहे अस्थायी बोर्ड



कब्जा करने वाली जगहों को खाली कराया जा रहा है। स्टॉल्स और अतिक्रमण को हटाने के बाद नो-वेंडिंग जॉन घोषित करते हुए वहां पर अस्थायी बोर्ड (सड़क

वेंडर्स न लौटें दोबारा, इसलिए की तैयारी

आरएमसी के अधिकारी की मानें तो सख्त निर्देशों के बावजूद फुटपाथ वेंडर्स या रोड किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेता अक्सर सड़कों पर लौट आते हैं, जिससे सड़कों को अतिक्रमण और भीड़भाड़ से मुक्त रखने के लिए ही नगर निगम ने नो वेंडिंग जॉन बनाते हुए सड़कों के किनारे से कब्जा हटाया है। अब अनधिकृत विक्रेताओं और स्टॉल वेंडर्स को भी हटाया जाना है। पूरे शहर को जाम मुक्त बनाने का निगम का यह अभियान जारी रहेगा। इसे लेकर निगम के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं नो वेंडिंग जॉन में दुकान लगाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा।

नो वेंडिंग जॉन को किया गया चिह्नित

अतिक्रमण को लेकर अभियान नियमित रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। जिनमें मेन रोड, लालपुर, हिन्दू, डोरंडा, कांटाटोली, कवहरी और बिरसा चौक शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारु बनाना और जनता को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। वहीं जाम नहीं लगने से लोगों ने भी थोड़ी राहत की सास ली है। वृत्ति पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ था ही नहीं। इन पर वेंडर्स ने कब्जा जमा रखा था। अब पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी है।

आई है। सड़क के किनारे भी लोगों को चलने की जगह मिल रही है। निगम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर नो-वेंडिंग और नो-पार्किंग एरिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। इस तकनीक की मदद से

अवैध रूप से पार्किंग करने या अतिक्रमण करने वालों पर नजर रखी जा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सड़क अतिक्रमण और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में : भाजपा

PHOTON NEWS RANCHI :

प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में है। पाकड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जारी है। माझी-पहाड़िया समुदाय का आरोप है कि मेला के बहाने कब्जे की साजिश की जा रही है। सरकार और प्रशासन मौन क्यों है। भाजपा ने सवाल खड़ा करते हुए आगे लिखा है कि क्या आदिवासी अपनी ही जमीन पर पराये बन जायेंगे? सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में प्रशासन विफल क्यों है। हेमंत सरकार से सवाल किया गया कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी? अवैध



निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी? प्रदेश भाजपा ने एक्स पर आगे लिखा कि झारखंड के आदिवासियों का हक छीना नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन आपकी चुप्पी, उनकी हिम्मत बढ़ा रही है! जनता सवाल पूछे, सरकार जवाब दे!

'अपार्टमेंट में बन रहे फ्लैटों के निबंधन में लाएं तेजी'

RANCHI : राज्य में अनिबंधित फ्लैट के निबंधन के लिए विशेष झूझ चलाया जायेगा। इसके लिए स्थानीय नगर निकाय से समन्वय करके अपार्टमेंटों की सूची तैयार की जा रही है, और यह देखा जा रहा है की इन अपार्टमेंटों में से कितने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। ऐसे फ्लैटों को चिह्नित किया जायेगा और इनके ऑनर से समन्वय करते हुए इनका निबंधन सुनिश्चित कराया जायेगा। निबंधन विभाग ने फ्लैटों की सूची तैयार करके निबंधन कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी सभी निबंधन पदाधिकारियों को दिया है। दरअसल, लगातार दो वित्तीय वर्षों से फ्लैटों के निबंधन में सुस्ती देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी धनबाद, रांची ग्रामीण, गिरिडीह, गढ़वा एवं जामताड़ा जिला में विगत वर्ष 2022-23 से कम संख्या में फ्लैट का निबंधन हुआ था।

भाजपा महानगर ने शुरू किया सदस्यता अभियान

PHOTON NEWS RANCHI :

शनिवार को भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर ने संगठन महापर्व सदस्यता अभियान अलबर्ट एक्का चौक पर एक भव्य शिविर लगाकर शुरू किया। शिविर का उद्घाटन भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद मौजूद रहे। राकेश प्रसाद ने सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन-जन की पार्टी है। यह विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए जन-जन को जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं से अपनी पूरी ऊर्जा

● राजधानी के अलबर्ट एक्का चौक पर लगाया गया शिविर ● बड़ी संख्या में शहर के युवाओं ने ग्रहण की सदस्यता



सदस्यता अभियान में शामिल लोग।

समर्पित करने का आह्वान किया। रांची विधायक सीपी सिंह ने भी संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के महत्व और उनके कर्तव्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी और

अपराधियों ने मोरहाबादी व हिन्दू की दो महिलाओं से ठगे 3.50 लाख रुपये के जेवर

RANCHI : शहर में अकेली महिला से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। हिन्दू और मोरहाबादी में ठग गिरोह ने दो महिलाओं को डराकर और ध्यान भटककर 3.50 लाख रुपए के जेवर ठग लिए। सेक्टर 2 धुवाँ की रहने वाली संगीता सिंह (50) ने कहा कि 26 दिसंबर को दिन में 11.30 से 12 बजे के बीच वह अपने घर से हिन्दू चौक के लिए निकली थी। ऑटो पकड़ने के लिए पथरकोचा बाईपास रोड से आगे बढ़ी तो चर्च के पास दो लोग बाइक से आए। एक कुछ दूरी पर रूक गया। दूसरे ने पास आकर कहा कि पुलिस चौक शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारु बनाना और जनता को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। वहीं जाम नहीं लगने से लोगों ने भी थोड़ी राहत की सास ली है। वृत्ति पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ था ही नहीं। इन पर वेंडर्स ने कब्जा जमा रखा था। अब पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी है।

डॉ.मनमोहन सिंह के योगदान ने देश को दी नई दिशा : प्रदीप यादव

PHOTON NEWS RANCHI :

शनिवार को रांची स्थित प्रदेश शिक्षक मुख्यालय में डॉ. मनमोहन सिंह कोर्स श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक विशाल व्यक्तित्व थे। उनके योगदान ने भारत को एक नई दिशा दी। 1990 के दशक में वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने देश को संकट से उबार आ और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत किया। उन्होंने हमें कहा कि डॉ. सिंह के नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक दृष्टि से प्रगति की, बल्कि उनका कार्यकाल



सामाजिक प्रगति और वैश्विक पहचान के लिए भी जाना जाता रहेगा। उनके द्वारा किए गए विनियमन, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाले कदमों ने भारत की विकास की नींव रखी। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक संकटों का सामना किया, जिसमें 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट प्रमुख था। अपनी दूरदृष्टि से उन्होंने भारत को

6 अधिकारी बनेंगे आइएस यूपीएससी ने लिया इंटरव्यू

RANCHI : झारखंड के नॉन एससीए (गैर राज्य सिविल सेवा) के 2020-21 व 2021-22 के बैकलॉग सहित कुल छह पदों पर प्रोन्नति देने के लिए यूपीएससी ने साक्षात्कार हुआ। कुल 21 अधिकारियों से इंटरव्यू लिया गया है, इनमें से छह का सलेक्शन आइएसएस के पद के लिए किया जायेगा। नई दिल्ली में हुए साक्षात्कार में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी व कार्मिक सचिव प्रदीप टोपो, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। राजेश प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, धनंजय कुमार सिंह, अलका जायसवाल, शिवेंद्र कुमार, सचिवालय देवेदु गिग्मा, आनंद कंचन सिंह, प्रीति रानी, सीता पुष्पा, सत्या ठाकुर, स्नेह कश्यप, शिप्रा सिन्हा, विकास कुमार, सुमंत कुमार तिवारी, विश्वजीत कुमार सिन्हा, कैप्टन एसपी सिन्हा, दीपक सहाय, समीर कुमार लकड़ा व विनय कुमार सिन्हा का इंटरव्यू लिया गया।

2023-24 व 24-25 सत्र को पूरी तरह नियमित करने का किया जा रहा प्रयास 39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस साल दिया गया स्कॉलरशिप का लाभ

PHOTON NEWS RANCHI :

कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा ने ई-कल्याण छात्रवृत्ति पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि वर्ष 2024 में दो चुनावों के बावजूद 39 और पोस्ट मैट्रिक के लिए 3.9 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है। जिसमें प्री मैट्रिक के 35,09,863 और पोस्ट मैट्रिक में 4,89,765 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। प्री मैट्रिक के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी 18,08,878 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। कल्याण आयुक्त ने आगे कहा है कि अगर शैक्षणिक सत्र और भुगतान को देखें तो यह याद रखना चाहिए कि 2022-23 में छात्रवृत्ति की ई-कल्याण पोर्टल पोस्ट मैट्रिक के लिए नहीं खुली थी और प्री मैट्रिक का भुगतान दिसंबर 2022 में शुरू हुआ। इस तरह ई कल्याण एक



शैक्षणिक सत्र पीछे हो गया था। इसे 2023-24 में और 2024-25 में पूरी तरह नियमित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्री मैट्रिक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों से आवेदन प्राप्त होते हैं और 2024-25 के लिए विद्यालयों से 28 लाख आवेदन आए हैं जिसमें से 18,08,878 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। प्री मैट्रिक के लिए आवेदन उपलब्ध है जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की समाप्ति से पहले और भी जितने आवेदन प्राप्त हों उन सभी का सम्पूर्ण भुगतान सम्पन्न कर दें। 2023-24 में 4,89,765 पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं को भुगतान हो चुका है। पिछड़ा वर्ग के लगभग 91 हजार छात्रों को भुगतान अभी किया जाना है, जिसके लिए माननीय मंत्री के अनुमोदन से 157 करोड़ राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

होगा एक्शन : प्रबंधन ने जारी किया नोटिस, हेल्पलाइन नंबर पर करें कंप्लेन

अब रिम्स में पैसे मांगने वाले दलालों की खैर नहीं

PHOTON NEWS RANCHI :

राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में आए दिन लोगों से पैसे मांगने की शिकायतें मिल रही हैं। कोई सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर परिजनों को ठग रहा है, तो कोई काम कराने के लिए पैसे मांग रहा है। अब रिम्स प्रबंधन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। इस पर रोक लगाने के लिए प्रबंधन ने योजना बनाई है। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिसपर लोग पैसे मांगने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं इटीग्रेटेड कंट्रोल् रूम में भी कम्प्लेन की व्यवस्था की गई है। इससे कि हॉस्पिटल में घुमने वाले दलालों पर रोक लगाई जा सके। रिम्स हॉस्पिटल में जगह-जगह पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि जन्म और मृत्यु से संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार से रुपये-पैसे का लेन-देन नहीं किया जाता है। जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र मुफ्त में बनाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति/कर्मि द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो तुरंत ही मोबाइल नंबर 9431938646, 9263614358 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसका अधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के पास या ऑफिस में भी से सुविधा कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट काउंटर नंबर 2,8,9 के साथ में स्थित इटीग्रेटेड कंट्रोल् रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आए दिन मरीजों और उनके परिजनों से पैसे मांगने की मिल रही शिकायत

- हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं दलाल, पैसे लेकर हो जाते हैं चपत
- इटीग्रेटेड कंट्रोल् रूम में भी की गई है शिकायत करने की व्यवस्था
- जगह-जगह पर लगाया गया नोटिस बोर्ड



यह भी दिया गया निर्देश

हॉस्पिटल में इलाज से लेकर दवाई भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन, कई बार दवाई उपलब्ध नहीं होने पर बाहर से मंगाई जाती है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ सटफ के लिए भी परिजनों से पैसे की मांग करते हैं। इसको लेकर भी प्रबंधन ने नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रिम्स में किसी भी तरह से पैसे का लेनदेन नहीं किया जाता है। अगर कोई इलाज या दवा के नाम पर पैसे मागे तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

21 दिनों में जारी किया जाता है सर्टिफिकेट

आवेदन के बाद 21 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। अगर पेपर में कोई गड़बड़ी हो तो इसमें अधिक समय लगता है। लेकिन, कुछ दलाल किस्म के लोग रिम्स में घूम रहे हैं। ये जल्दी काम कराने के एवज में पैसे ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बाद आवेदन करने वाला काउंटर के चक्कर लगाता रहता है। काउंटर पर पहुंचने पर जानकारी मिलती है कि अभी सर्टिफिकेट तैयार नहीं है। ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लगती है।

झारखंड पुलिस में नहीं हो रही साप्ताहिक परेड

RANCHI : झारखंड के विभिन्न जिलों में पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक परेड का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इसको लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने आदेश जारी किया है। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी अभियान ने सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किया है कि वे नियमित रूप से साप्ताहिक परेड का आयोजन सुनिश्चित करें। साप्ताहिक परेड का आयोजन नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। साथ ही नियमित परेड से पुलिसकर्मी शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। परेड न होने से उनकी शारीरिक दक्षता में कमी आ रही है। इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिला, इकाई और वाहिनी में प्रत्येक साप्ताहिक कम से कम एक दिन परेड का आयोजन अनिवार्य है।

रिम्स के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स पहुंचे नई दिल्ली



PHOTON NEWS RANCHI :

रिम्स के हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट्स ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 19 से 21 दिसंबर तक कांफ्रेंस में भाग लिया। तीन दिवसीय इस कांफ्रेंस का विषय था सेफ एंड स्टर्नेबल हॉस्पिटल (रअरल 2024)। इसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। जिनमें एम्स दिल्ली, एसजीपीजीआई लखनऊ और केजीएमयू मणिपाल जैसे शीर्ष मेडिकल संस्थान शामिल थे।

स्टूडेंट्स ने कांफ्रेंस में उपस्थित विशेषज्ञों से संवाद किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त की। स्टूडेंट्स ने इफेक्ट्स आफ लीगल एंड रेगुलेटरी बाँडी आन आटोनामी आफ ए मेडिकल इंस्टीट्यूट: ए रेगुलेटिव स्टडी विषय पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एम्स नई दिल्ली का भी भ्रमण किया। यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा।

पहले बोकारो में हुआ था उपचार, रांची के देवकमल अस्पताल में हुई मौत हजारीबाग के सदर एसडीओ की पत्नी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

PHOTON NEWS HAZARIBAGH :

शुक्रवार की देर रात हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनिता कुमारी की मौत रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुरुवार को हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनिता कुमारी ने साधारण विवाह में खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। वह 65% जल गई थी। पहले उनका इलाज बोकारो में हुआ था उसके बाद उन्हें रांची रेफर किया गया था। जानकारी के अनुसार, उन्हें बचाने गए एसडीओ के भी दोनों हाथ जल गए थे। यह मामला शुक्रवार को उस समय और गरमा गया, जब एसडीओ की पत्नी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने लोहसिंघना थाना में आवेदन देकर एसडीओ और उनके परिजनों पर उनकी बहन को जलाने का आरोप लगाया। राजू गुप्ता ने आरोप

साला ने जीजा और परिवार के अन्य लोगों पर पर दर्ज कराया केस

एसडीओ ने दी थी यह जानकारी

अशोक कुमार ने बताया कि आवास में पेंटिंग का काम चल रहा है। पत्नी को मॉनिंग वॉक पर जाने से मना किया। इसके बाद हम दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद अचानक अनिता ने आवास परिसर में रखे पेट के तेल को छिड़कर आग लगा ली। आग बुझाने का मैंने प्रयास किया। उसे तुरंत आरोप्यम हॉस्पिटल ले गया। अनिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए, वहां से बेहतर इलाज के लिए बोकारो भेजा गया। वहां से रिम्स रेफर किया गया।



दोनों के बीच होता रहता था विवाद

मृतका के भाई राजू गुप्ता क्या कहना है कि मेरी बहन बार-बार बोलती थी कि मेरे पति अशोक कुमार का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। एक बार इस मामले में हमारे परिवारवालों ने अशोक कुमार के परिवारवालों के साथ बैठकर बातचीत की। इसके बाद अशोक कुमार ने कहा कि अमली बार से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

● जलाकर मारने का लगाया आरोप, दूसरी महिला से संबंध की बताई बात

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : प्रदर्शन के दौरान कड़वी सुरक्षा का इंतजाम थाने के आसपास किया गया था, दूसरी ओर सुबह सदर एसडीओ अशोक कुमार के आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई मजिस्ट्रेट के रूप में सदस्यों को तैनात किया गया है। एसडीओ के पिता ने आरोप को बताया निराधार : एसडीओ अशोक कुमार के पिता दुर्गोबिंद कुमार ने कहा कि पूरा आरोप निराधार है। पति-पत्नी के बीच में मधुर संबंध थे। घटना कैसे हुई, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। परिवारवालों ने बताया है कि सुबह 6:30 बजे अलाव तापने के दौरान कपड़े में आग लगने से यह घटना घटी है।



सज गई फूलों की बगिया

जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक 34वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी लगी है। यहां देश-विदेश की विभिन्न प्रजातियों के फूल, औषधीय पौधे व बोनाईस का आनंद सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक उठाया जा सकता है।

BRIEF NEWS

चौकीदार परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी

HAZARIBAGH : हजारीबाग जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 20 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औपबधिक सूची जारी कर दी गई है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि इस सूची में यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी 30 दिसंबर को शाम 5 बजे तक समाहरणालय भवन के ग्राउंड फ्लोर पर कमरा संख्या-001 में स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दावा-आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत शारीरिक माप एवं जांच से संबंधित सूचना प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए 8 खिलाड़ी रवाना



CHAI BASA : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 30-31 दिसंबर को 7वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए चाईबासा स्थित बिरसा मुंडा ताइक्वांडो एकेडमी के 8 खिलाड़ी शनिवार को रवाना हुए। एकेडमी के कोच विजय प्रताप ने बताया कि इसमें झारखंड से 32 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चाईबासा से जाने वाली टीम में छह पुरुष व दो महिला खिलाड़ी हैं।

अधिकार पाना है तो चार बच्चे पैदा करें विस्थापित : जयराम

PHOTON NEWS BORMO :

विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति, बेरमो का एक दिवसीय सेमिनार शनिवार को बिनोद बिहारी महतो फुटबल ग्राउंड, करगली में हुआ। यहां मुख्य अतिथि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे चार की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। दो बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें, ताकि वे अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सकें। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले-भाले लोग हैं, जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घिस-घिस कर लड़ रहे हैं। कहा कि विस्थापित कई समूहों में विभाजित हैं। सभी को निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन यहां के विस्थापितों का शोषण बंद हो जाएगा। कहा कि हम अपनी जान को हथेली पर रख कर चल रहे हैं, ताकि झारखंड की अगम की आवाज बन सकें और उन्हें न्याय दिला सकें। कहा कि विस्थापितों की जमीन से निकलने वाला कोयला लूटकर यहां के माफिया राज कर रहे हैं और विस्थापित अधिकार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कहा कि माफिया के हासले बुलंद हैं, उसे कुचलना होगा और पूरे झारखंड से भगाया होगा। कहा कि प्रशासन भी सीसीएल की तरफदारी करता है। प्रशासन की नाक के नीचे विस्थापितों की जमीन को लूटकर उनके संवैधानिक अधिकारों पर रोज हमले हो रहे हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। कहा कि छह

● सेमिनार में बोले डुमरी विधायक हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे चार की तर्ज पर चले विस्थापित, दो को बनाए दिवंगी



जनवरी से आहत बेमियादी चक्काजाम आंदोलन में वे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इसमें छह जनवरी से सीसीएल दोरी, बीएंडके व कथारा परिया के बेमियादी चक्का जाम आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष लखनलाल महतो ने कहा कि विधायक जयराम महतो जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, उसी तेवर के साथ विधानसभा में विस्थापितों की भी आवाज उठाने का काम करें। पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्थापित आयोग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह आयोग नहीं बना। कहा कि बहुत सी बातों को जेबीसीसीआइ में कोल इंडिया अध्यक्ष के सामने उठाया गया था। इसमें दो एकरड की सीलिंग को खत्म कर, जिनको 10-20 डिसेमिल व एकरड में जमीन और मकान है, उन्हें भी नियोजन देते हुए सीलिंग हटाने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर प्रबंधन द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है।

स्थापना दिवस पर निकाली रैली, सीएम के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

एआईडीएसओ ने रखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करने की मांग

PHOTON NEWS GHATSHILA :

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के 71वें स्थापना दिवस पर शनिवार को साकची के आमबगान मैदान से रैली निकली, जो उपायुक्त कार्यालय तक गई। यहां छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष युधिष्ठिर कुमार ने बताया कि उनकी मांगों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रद्द करने, रिक्त पदों पर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली करने, छात्रों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने, निजी स्कूलों में लगातार फीस वृद्धि व अन्य खर्चों पर रोक लगाने, नशाखोरी, पोर्नोग्राफी और शराब दुकानों पर पूर्ण पाबंदी लगाने, छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने आदि शामिल हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि एआईडीएसओ अपने स्थापना काल से ही जनवादी धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा की मांग को लेकर छात्रों को संगठित कर रहा



रैली में शामिल लोग।

● फोटोन न्यूज

है। छात्र और शिक्षा प्रेमियों की यह लड़ाई सिर्फ शिक्षा बचाने की ही नहीं, सभ्यता और इंसायनित बचाने की भी है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक बढ़ावा देने पर चरम पर है। शैक्षिक प्रशासन को समग्र रूप से केंद्रीकृत करने का सरकार का प्रयास शिक्षा के मामलों को पूरी तरह से निरंकुश तरीके से नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। जिला सचिव शुभम झा ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने तथा शिक्षा

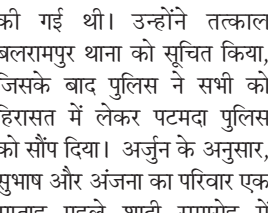
का संपूर्ण व्यवसायीकरण करने की नीति है। इस नीति का उद्देश्य आजादी के बाद से शासक वर्ग द्वारा शिक्षा पर किए गए लगातार हमलों के बाद भी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और वैज्ञानिक शिक्षा के बचे-खुचे अवशेषों को मिटा देना है। नई शिक्षा नीति का ही नतीजा है। कि स्कूल-कॉलेजों और केन्द्रीय सहित सभी विश्वविद्यालयों में बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। आज शिक्षा को बचाने के लिए छात्रों को संगठित होने की जरूरत है।

महिला ने पति की हत्या कर ससुराल में छोड़ा शव

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत केरुआ गांव में एक महिला ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बलरामपुर स्थित ससुराल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर निवासी 40 वर्षीय सुभाष सहिस की शादी 15 वर्ष पहले पटमदा के केरुआ गांव की अंजना सहिस से हुई थी। हाल ही में, सुभाष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंजना की चचेरी बहन की शादी में शामिल होने केरुआ गांव आया था। इसी दौरान, किसी विवाद में सुभाष की हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे अर्जुन ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अंजना और उसके पिता काली साहिल, भाई आनंद सहिस और बहन चंद्रना सहिस घर पहुंचे थे। सुभाष के शरीर पर चोट के निशान थे और वह मृत अवस्था में था। जांच में पता चला कि किसी विवाद के चलते सुभाष की हत्या

● मारके में भाई-बहन और पिता के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम



की गई थी। उन्होंने तत्काल बलरामपुर थाना को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पटमदा पुलिस को सौंप दिया। अर्जुन के अनुसार, सुभाष और अंजना का परिवार एक सप्ताह पहले शादी समारोह में शामिल होने केरुआ गांव आया था। उसी दौरान, किसी बात को लेकर सुभाष और अंजना के परिवार के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सुभाष को पिटाई की गई और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सुभाष की पहली पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उसने दूसरी शादी की थी। सुभाष मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।

नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

PHOTON NEWS DUMKA :

जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के एक 16 वर्षीय आदिवासी युवती ने निकटवर्ती धावाटांड गांव के जीतन मुर्मू पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने अप्रैल 2023 में 20 से अधिक बार उसके साथ गलत काम किया है। बताया जा रहा है कि आरोपित नाबालिग को जंगल में गाय चराने के दौरान में दुष्कर्म करने के बाद वीडियो भी बनाया करता था। इसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को आए दिन ब्लैकमेलिंग किया करता था। साथ ही



उसे परिवार सहित जान से मारने और घर जला देने की धमकी देता था। इतना ही नहीं आरोपित युवक पीड़िता को कहीं शादी नहीं होने की धमकी देता था। आरोपित की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने चुपकी तोड़ते हुए जरमुंडी थाना पहुंच कर अपनी आपबीती सुनाते हुए दोषी को कठोर सजा देने की गुहार लगाई।

ग्रामीणों ने 45 गोवंशीय पशुओं से लदे ट्रक को किया पुलिस के हवाले

GIRIDIH : निमियाघाट थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) के बड़कीटांड के निकट ग्रामीणों ने शनिवार को 45 गोवंशीय पशुओं से लदे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाकत डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि उक्त वाहन में 45 से अधिक गोवंशीय पशु लोड है। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए पंचायत के मुखिया ने बताया गया कि शनिवार को अहले सुबह क्षेत्र में टहल रहे थे कि एक कंटेनर जिसकी टायर पंचर हो जाने के कारण खड़ी थी।



पूर्व पीएम मनमोहन को दी गई श्रद्धांजलि

शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बिष्टुपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय (सिलाक पुस्तकालय) में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय झा, शकेल तिवारी, चंद्रमान सिंह, खगेनरचंद्र महतो, अंसार खान आदि ने डॉ. सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।

उत्पाद निरीक्षक प्रवीण चौधरी की घर पर संदेहास्पद स्थिति में मौत

PHOTON NEWS CHAIBASA :

चाईबासा में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रवीण चौधरी की शनिवार को संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना शनिवार दोपहर 12.30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, उत्पाद निरीक्षक चाईबासा के छोटा नीमडीह स्थित किराए के मकान में रहते थे। शनिवार को दोपहर में जब उनके घर पर मेड पहुंची तो उसने देखा कि प्रवीण चौधरी फर्श पर गिरे हुए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन होश में थे।



नौकरानी ने चौधरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें लग रहा है कि वह नहीं बच पाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द इलाज

के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाए या फिर डॉक्टर को बुलाया जाए। इसके बाद नौकरानी ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी देते हुए मदद करने का आग्रह किया। स्थानीय लोग बिना देर किए प्रवीण चौधरी को चाईबासा के सदर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वैसे कुछ लोग उनकी मौत की वजह हृदयाघात भी बता रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही सही जानकारी मिलने की उम्मीद है।

सुविधा : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सदर अस्पताल में शुरू हुई ऑनलाइन सेवा

दंत रोग विभाग में ई-प्रिसक्रिप्शन शुरू, मरीजों को मिलेगी राहत

PHOTON NEWS DHANBAD :

सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पेपरलेस करने की तैयारी के तहत सदर अस्पताल में काम शुरू हुआ है। दंत रोग विभाग में ई-प्रिसक्रिप्शन सेवा शुरू हुई है। दंत रोग विभाग में मरीजों को मेनुअल पर्ची काटने का झंझट खत्म हो गया है। ऑनलाइन पर्ची काट कर दंत रोग विभाग में भेजा जा रहा है। इसी पर्वी को देखकर दंत रोग चिकित्सक मरीज का इलाज कर रहे हैं। हर दिन दंत रोग विभाग में 15 से 20 ई-प्रिसक्रिप्शन बनने लगे हैं। आयुष्मान योजना के तहत प्रयोग के तौर पर दंत विभाग में यह सेवा शुरू की गई है। डिजिटल मिशन के जिला समन्वयक रिसका सिन्हा ने बताया कि आगे मेडिसिन विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, नाक कान व गला रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग में भी यह सेवा शुरू करनी है। उन्होंने बताया कि पहले ओपीडी में यह सेवा पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। इसके बाद वार्ड में रहने वाले मरीजों के लिए इंडोर में यह सेवा शुरू होगी।

मरीजों की दवा, बीमारी व इलाज से संबंधित तमाम जानकारियों का रहेगा रिकॉर्ड

- मेडिसिन विभाग स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग नाक कान व गला रोग विभाग नेत्र रोग विभाग में भी यह सेवा शुरू करने की हो रही तैयारी
- मेडिकल कॉलेज में डिजिटल मिशन का केंद्र खोलने की तैयारी



मेडिकल कॉलेज में नई सेवा शुरू करने को लेकर बैठक

आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल कॉलेज में भी यह सेवा शुरू की जाएगी। पिछले दिनों आयुष्मान भारत राज्य स्तरीय टीम ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर-के इसे शुरू करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज में डिजिटल मिशन का केंद्र खोलने की तैयारी हो रही है। अधीक्षक डॉ. संजय कुमार चौरसिया ने बताया कि केंद्र में अलग से कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई सेवाएं यहां शुरू होने वाली हैं। इसका सीधा लाभ आने वाले दिनों में मरीजों को मिलेगा।

अस्पताल में दूर होगी फाइल की समस्या

आयुष्मान मिशन का उद्देश्य अस्पतालों में भारी भरकम फाइल की समस्या को दूर करना है। मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ओपीडी में पर्ची कटनी होती है। इसलिए लंबी लाइन से छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर से दिखाने से लेकर पैथोलॉजी विभाग में खून जांच कराना हो या रेडियोलॉजी विभाग में किसी अन्य जांच, सब जगह पेपरलेस काम होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होकर डॉक्ट बन जाने से, ऑनलाइन व्यवस्था के साथ मरीज की सभी जानकारी और डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। मरीज की दवा बीमारी और इलाज से संबंधित तमाम जानकारी भी यहां इकट्ठी होगी, ताकि मरीज को बेहतर जांच के साथ इलाज की सुविधा मिल पाए।

स्वपरिखा पुल से कूद कर किशोरी ने की आत्महत्या

GHATSHILA : थाना क्षेत्र के मऊभंडार स्थित स्वपरिखा नदी के पुल से कूद कर शनिवार को एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबूलाइन के सर्वेक्ट क्वार्टर में रहने वाली किशोरी दोपहर में पुल पर जा रही थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, किशोरी ने छलांग लगा दी। लोगों ने तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन दे दल-बल के साथ नदी किनारे पहुंचकर किशोरी को उठाकर अनुमंडल अस्पताल लाया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मां ने बताया कि वह मोबाइल फोन छीन लेने के बाद से गुस्से में थी। आज अचानक घर से बिना किसी को बताए निकली थी।

प्रवीण तोगड़िया कटक में किए गए सम्मानित



PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया शनिवार को कटक (ओडिशा) में शनिवार को क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें यह सम्मान वीर सावरकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व जमशेदपुर निवासी धर्म चंद्र पोद्दार ने प्रदान किया। संस्था के अध्यक्ष प्रहलाद खडेलवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया ने

हिंदुओं को संगठित होने का आह्वान किया। महासचिव श्याम सुंदर पोद्दार ने कहा कि जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराया, उनको श्रेय नहीं दिया गया, बल्कि बदनाम किया गया। इस अवसर पर कौशल पोद्दार, संगीता पोद्दार, शीतल पोद्दार, नंदकिशोर जोशी, किशन लाल बाजला, दिलीप कुमार मोदी, उमा शंकर, दिलीप, अनुराधा मोदी, गीता चवनी, संतोष देवता, सबिता दास आदि भी उपस्थित थे।

सहज ऋण प्रवाह ने बदली ग्रामीण जीवन शैली

वित्तदायी संस्थाओं तक आम आदमी की सहज पहुंच और संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तदायी संस्थाओं द्वारा आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का परिणाम है कि आज देश के सुदूर गांवों में भी रहन-सहन में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरों में उपलब्ध सुविधाएं अब गांवों में सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों की रहन-सहन और उनकी सोच में बदलाव आया है। आज कोई भी व्यक्ति साधन-सुविधाओं की ओर देखाता है और उन सुविधाओं को पाने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो व्यक्ति दो बार सोचता नहीं। यही समय और सोच का बदलाव है। सांख्यिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट इस बात की गहराई से पुष्टि करती है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की व्यापक वार्षिक माइजूरल रिपोर्ट के अनुसार, शहरों की तुलना में अब गांवों में ऋण लेने वाले अधिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में प्रति एक लाख पर 18714 लोगों ने किसी ना किसी तरह का कर्ज लिया है, वहीं शहरी क्षेत्र का यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कुछ कम 17442 है। अच्छी बात यह है कि अब संस्थागत ऋणों की उपलब्धता सहज हो गई है पर गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं ने भी तेजी से पांव पसार रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि इन गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं में कहीं ना कहीं पुराने साहूकारों की झलक दिखाई देती है। दूसरी चिंता का कारण संस्थागत ऋण में भी इस तरह के ऋणों की ब्याज दर कहीं अधिक है और संस्थागत हो या गैर संस्थागत ऋण, प्रदाता ऋण की एक किश्त भी समय पर जमा नहीं होती है तो दंडनीय ब्याज वसूली के नाम पर संपर्क और पत्राचार आदि का खर्चा और इसी तरह के अन्य छुपे चार्जेज ऋण लेने वाले की कमर तोड़ने के लिए काफी हैं। इसमें दो राय नहीं कि शहरी नागरिकों की तरह ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर और रहन-सहन में सुधार होना चाहिए। शहरों से किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण पीछे नहीं रहने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों और शहरियों में जीवन स्तर को लेकर जो स्तरीय भेद सामने आता है वह दिन प्रतिदिन कम रहा है। आज फ्रीज, एयर कंडीशनर, महंगे एंड्राइड मोबाइल या लकजरी वाहन आसानी से गांवों में देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो आज पहले वाले गांव नहीं रहे। यह विकास की तस्वीर है। यहां तक कि गांवों में निजी स्कूलों का पहुंच भी हो गई है। आज ग्रामीण भी शहरी शैली अधिकतर ऋण धरें लू जल्द करतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, खानपान और शानोशौकत से रहने के लिए पहनावे आदि के लिए लिया जाता है। गांव और शहरों में एक अंतर यह है कि शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्तर पर आसानी से उपलब्ध है, वहीं गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को ऋण लेना पड़ता है। यह सब कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण से अलग हट कर है। वैसे भी अधिकांश स्थानों पर संस्थागत कृषि ऋण लगभग जीरो ब्याजदर पर या नाममात्र के ब्याज पर उपलब्ध होता है पर नकारात्मक पक्ष यह है कि बिना ब्याज के ऋण को समय पर नहीं चुका कर कर्ज माफ़ी के राजनीतिक जुमले के चलते जीरो ब्याज सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। खैर यह विषय से भटकना होगा। शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से संपन्न हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विकास की गंगा भी सभी तरफ समान रूप से बहनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सबका सपना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ते कर्ज के पीछे जो चिंतनीय बात है, वह यह है कि कहीं ग्रामीण कर्ज के मकड़जाल में फंस कर कुछ पाने की जगह खो अधिक देंगे, इसकी आशंका अधिक है। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण हों या फिर गैर संस्थागत ऋण, परेशानी इनकी वसूली व्यवस्था को लेकर होती है। जितने ऋण देते समय सहज्य होते हैं, ऋण की किश्त की वसूली के समय उत्तरे ही बेदर्द होने में कोई कमी नहीं रहती। शहरों में आए दिन रिकवरी एजेंटों के व्यवहार से दो-चार होते देखने में आ जाते हैं। गांवों में तो वसूली करने वालों के टांचर के हालात बदतर ही होंगे। ऐसे में समय रहते इसे विचार में सोचना होगा। सरकार और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के सामने बड़ी जिम्मेदारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की है। दरअसल, जब ऋण प्रदाता संस्था से ऋण लिया जाता है तो उस समय जो डाक्यूमेंट होता है वह इतना बड़ा और जटिल होता है कि उसे पूरा देखा ही नहीं जाता है और ऋण दिलाने वाला व्यक्ति निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देता है। पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्ति भी पूरे डाक्यूमेंट से गो ध्रू नहीं होता और परिणाम यह होता है कि बाद में दस्तावेज के प्रावधानों के कारण दो-चार होना पड़ता है। हस्ताक्षर करने से हाथ बंध जाते हैं।

क्या कांग्रेस का 'वामपंथीकरण' ही राहुल की नई राजनीति होगी

ANALYSIS



कमलेश पांडेय

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि इसका मकसद है यह पता लगाना कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो यह भारत का पहला काम होगा। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्याय मंच-अब इंडिया बोलेगा में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद उनका पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ जाति जनगणना करवाना होगा। उन्होंने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है और वे इस बात से भी अनजान हैं कि उनके पास भारत की कुल संपत्ति में से कितनी संपत्ति है। वे कहते हैं कि उनकी आबादी लगभग 50 प्रतिशत है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इसलिए हम एक जाति जनगणना करेंगे, जिससे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पता चल जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कितनी भागीदारी है। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इससे दलित, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीब सवर्णों को भी उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी सरकार आई तो सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं, बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। दरअसल, इसके जरिए यह पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। फिर नई राजनीति शुरू होगी। इससे साफ है कि जेएनयू के युवा वामपंथी नेताओं व कार्यकर्ताओं से भरी कांग्रेस अब उस वामपंथ की राह पर अग्रसर है, जो पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुका है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि इसका मकसद है यह पता लगाना कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो यह भारत का पहला काम होगा। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्याय मंच-अब इंडिया बोलेगा में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद उनका पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ जाति जनगणना करवाना होगा। उन्होंने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है और वे इस बात से भी अनजान हैं कि उनके पास भारत की कुल संपत्ति में से कितनी संपत्ति है। वे कहते हैं कि उनकी आबादी लगभग 50 प्रतिशत है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इसलिए हम एक जाति जनगणना करेंगे, जिससे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पता चल जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कितनी भागीदारी है। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इससे दलितों,



अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीब सवर्णों को भी उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। वहीं, एक युवा के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज क्या हो रहा है कि ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है और उन्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। जाति जनगणना के साथ साथ होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण से पूरे देश को यह पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, अल्पसंख्यकों के हाथ में कितना, गरीब सामान्य वर्ग और महिलाओं के हाथ में कितना धन है। सबके सामने पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद न्यू पॉलिटेक्निक शुरू होगी। उसके बाद ये लोग कहेंगे कि मेरे पचास परसेंट लोग हैं, जबकि मेरे पास 2 परसेंट धन है। इसलिए मुझे 50 परसेंट धन चाहिए। सीधी-सी बात होगी। ये हमारी सोच है, जाति जनगणना पहला कदम है। ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगी, बल्कि ये आर्थिक सर्वे भी होगा। हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अब साफ है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जागीरदारी पुनः पाने के लिए जिस तरह से ओबीसी, दलित, आदिवासी, गरीब सवर्ण और महिलाओं को उनके हिस्से की संपत्ति मौजूदा अमीरों से लेकर देना चाहते हैं, उससे विदेशी निवेश प्रभावित होगा। धनी लोग अपनी संपत्ति विदेशों में शिफ्ट करने लगेंगे। इससे हर ओर असंतोष फैलेगा और देश में अरब देशों की तरह गृह युद्ध होगा, क्योंकि इतनी आसानी से लोग अपनी संपत्ति छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि देश में अब ग्राम भूमि सवर्णों से ओबीसी-दलितों-अल्पसंख्यकों-आदिवासियों की ओर हस्तांतरित होती जा रही है। यह कांग्रेस की सरकारों की नीतियों और उनको हटाकर विकसित हुई समाजवादी राजनीति करने वाले दलों की नीतियों की करामत है। वहीं, शहरों को भी शिफ्ट हो रहे सवर्णों के पास शहरी संपत्ति बढ़ी है, लेकिन

ओबीसी-दलितों-आदिवासियों-अल्पसंख्यकों आदि ने भी ऐसी नई संपत्ति खूब बनाई है। इससे संपत्ति के समान बंटवारे का उनका विचार पिछले लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही उन पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि तब वह केंद्रीय सत्ता में आते-आते यदि चूक गए तो उसके पीछे उनसे इन्हें बयानबाजियों का हाथ है। देखा जाए तो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में जातीय आरक्षण जैसे निकट विचार के बाद जनसंख्या आधारित संपत्ति के बंटवारे का विचार कांग्रेस का ऐसा जाहिल विचार है, जो भारत के विकास को पुनः अवरूद्ध कर देगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस रणनीतिकार चीनी-रूसी साठगोट से प्रभावित और सीआईए-आईएसआई के बैक डोर पॉलिसी आधारित षड्यंत्रों से अनुप्राणित हैं, जिनका मकसद है कि अमेरिका, रूस, चीन के समकक्ष स्तर तक उठ चुके मोदी युगिन भारत को उलजुलुल सिपासी विवादों में फंसाकर पीछे धकेल दिया जाए। यदि इसे समझने में राहुल गांधी नादानि दिखा रहे हैं तो यह एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड है, जिस ओर भाजपा भी इशारा कर चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की मांग पर अड़े रहने से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2029 में बहुमत भी मिल सकता है, क्योंकि मुफ्तखार राजनीति एक बार फिर से परवान चढ़ती जा रही है। जब हजार-दो हजार की गारंटी देने वाले दलों पर मतदाता फिदा हो सकते हैं, तो यहां पर तो राहुल गांधी संपत्ति ही देने-दिलाने के कोरे आश्वासन दे रहे हैं। वैसे भी फ्री उपहार की राजनीति आप, कांग्रेस होते हुए यह भाजपा व

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

एयर स्ट्राइक करना बंद अंधेरी सुरंग में घुसने जैसा

पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों की 24 दिसंबर की रात अफगानिस्तान के पूर्वी पाकटीका प्रांत में एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान में तहरीक-ए-ताल्लिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 4 आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने का दावा किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी कमांडर शेरा जमान, कमांडर अबू हमजा, कमांडर अख्तर मुहम्मद और टीटीपी का मीडिया संगठन उमर मीडिया इन ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था। इस एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की ताल्लिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले में महिलाओं और बच्चे समेत 15 निर्दोष नागरिकों की जान जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, ताल्लिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगान रक्षामंत्री मुल्ला

याकूब ने इस हमले का कराार जवाब देने की पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली है, जिससे पाकिस्तान-अफगान बॉर्डर पर भारी तनातनी है। दुनिया को याद है कि इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तानी सरकार ने 15 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में ताल्लिबानी शासन की वापसी पर जिस तरह उसका खैर मकदम किया था, उससे उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों का गठजोड़ आतंकों के नया मोर्चा साबित होगा। खासतौर पर भारत इसे लेकर सतर्क था। पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ अफगानिस्तान की ताल्लिबान सरकार के साथ खड़ा था कि नया निजाम तहरीक-ए-ताल्लिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। अफगानिस्तान समेत 15 निर्दोष नागरिकों की जान जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, ताल्लिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगान रक्षामंत्री मुल्ला



पाकिस्तान के भीतर लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान में ताल्लिबान के कार्रबाज होने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी की एक्टिविटी बढ़ गई है। बीते दो साल में खैबर पखूनख्वाह और बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएँ ज्यादा बढ़ी हैं। इसकी वजह ये है कि ये अफगानिस्तान बॉर्डर के ज्यादा पास हैं। हालत यह है कि इस साल नवंबर तक टीटीपी पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत खैबर पखूनख्वाह और बलूचिस्तान में 785 हमलों को अंजाम दे चुका है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 951 फौजियों की मौत हो गई,

जबकि 966 लोग जख्मी हुए। टीटीपी के इन तमाम हमलों से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना की खासी फजीहत हुई, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पहले ही सौंपैक, बलूचिस्तान में बगावत और इमरान खान के समर्थकों से निबटने में बुरी तरह विफल रही है, लेकिन टीटीपी ने हाल ही में जब वजीरिस्तान के मकीन में पाकिस्तान के 30 फौजियों को मार गिराया, तो उसने पाकिस्तानी सेना को टीटीपी के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक न की

होती तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए अपनी सेना का मनोबल बनाए रख पाना मुश्किल था। हालांकि, आर्मी चीफ को अंदाजा रहा होगा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक उसके लिए बंद अंधेरी सुरंग में घुसने जैसा है, जिससे गुजरकर दुनिया की दो सुपर पावर रूस और अमेरिका की फौजें शिकस्त खा चुकी हैं। पाकिस्तान की फौजी ताकत और संसाधन, रूस और अमेरिका के मुकाबले क्या हैं, यह सभी को पता है। अफगान ताल्लिबान से अलग टीटीपी तहरीक-ए-ताल्लिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाकिस्तानी ताल्लिबान भी कहते हैं। इसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना है। अगस्त 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था, लेकिन इसकी गतिविधियों को रोक पाने में विफल रहा। हमलों की फेहरिस्त देखें तो साल 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल और साल 2009 में सेना

मुख्यालय पर टीटीपी की तरफ से हमला किया गया था। 2012 में मलाला युसुफजई को निशाना बनाने पर पूरी दुनिया का ध्यान इस संगठन को ओर गया। इसी आतंकी संगठन ने टीटी 2014 में सबसे बर्बर और वीभत्स हमले को अंजाम दिया, जिसमें पेशावर के सैनिक स्कूल में 150 लोगों मार दिया, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। नवंबर, 2021 में पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच सीफायर समझौता भी हुआ, जिसमें टीटीपी ने उसके समर्थकों को जेल से रिहा करने की मांग की थी। साथ ही कबायली इलाकों से पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को हटाने की मांग की गई, लेकिन यह समझौता महीने भर बाद ही टूट गया। इसके बाद एक साल तक सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत होती रही और कोई समझौता न होने पर टीटीपी ने फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तान में जहां भी संभव हो, उसके लड़ाके हमला करें।

Social Media Corner

सब के हक में...

बटिंडा, पंजाब में एक बस दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार से मुझे गहरा दुख हुआ। मैं सभी शोक सप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस दुर्घटना में घायल हुए सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों।



(राष्ट्रपति दीपदी मुर्मू का 'एक्स' पर पोस्ट)

रतन टाटा जी की जयंती पर, हम दूरदर्शी विज्ञान से लीडर को याद करते हैं। रतन टाटा जी ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से भारत के व्यापार परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया और अपनी परिपक्वारी पहलों से लोगों के जीवन में बदलाव लाया। वह नए जमाने के उद्योगियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बने रहेंगे।



(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड की अबुआ सरकार समुदाय विशेष के लोगों को जमीन विवाद से जुड़े मामलों में खुला संरक्षण दे रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को झुठाना पड़ रहा है। पाकडू में समुदाय विशेष के द्वारा सरकारी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण करना दर्शाता है कि इन्हें किस हद तक सरकार का संरक्षण प्राप्त है। संताल परगना समेत पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं।



(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

संवैधानिक लोकतंत्र और भारत की आत्मा

लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक उम्मीद की खिड़की खुली थी। संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के सामने जो दीवार खड़ी हुई थी, उसमें एक खिड़की खोलने का काम जनता ने किया था। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव की तरह जनता ने 2024 में भी एक दीवार में खिड़की खोलकर विपक्षी पार्टियों को मौका दिया था कि वह इसे दरवाजा बना सकें, और उस रास्ते से देश बचाने की लड़ाई लड़ सकें। पर भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि अक्सर पार्टियाँ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी संपाल नहीं पातीं। छह महीने के भीतर तीन विधानसभा चुनावों के बाद यह खिड़की सिक्कड़कर एक रोशनदान भर रह गयी है। जिम्मेदारी अब फिर जनता और जन संगठनों पर आन पड़ी है कि वे भारतीय संविधान की आत्मा को बचाने का संघर्ष तेज करें। रोशनी की इस खिड़की के जरिए दरवाजा खोलने के लिए झरसी था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले धक्के को उसकी पराजय के सिलसिले में बदला जाए। लोकसभा के बाद के तीनों चुनावों में यह काम असंभव नहीं था। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहां विधानसभा का चुनाव जीता हुआ माना जा रहा था। हरियाणा में लोकसभा की सीटें पांच-पांच में बंटी थीं, पर विधानसभा के संदर्भ में यह मानना

स्वाभाविक था कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। झारखंड में मामला कठिन था। चूँकि लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगियों का पलड़ा भारी था, फिर भी लगता था कि कोशिश की जाए, तो झामुमो और सहयोगियों की जीत संभव है। वास्तव में हुआ इसका उलटा। जिस झारखंड में जीत सबसे कठिन थी, वहां इंडिया गठबंधन धड़ल्ले से जीता। हरियाणा में जहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था, वहां हार गई और जिस महाराष्ट्र में चुनाव जीता-जिताया लग रहा था, वहां इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया। बेशक यह चुनाव परिणाम विवाद से परे नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विपक्ष ने चुनाव परिणाम पर उंगली उठायी है। पिछले 35 साल से चुनावी जीत-हार देखते हुए मुझे भी पिछले साल मध्य प्रदेश के आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम की तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में दाल में कुछ काला दिखाता है। एक बात तय है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के जो तेवर ढीले पड़े थे, उसमें अब बदलाव आयेगा। इसका संकेत महाराष्ट्र की विजय के बाद संसद सत्र की शुरूआत में प्रधानमंत्री के बयान से ही लग जाता है। अब भी भाजपा के लिए संविधान बदलना या संविधान बदलने जैसी वन नेशन-वन इलेक्शन योजना लागू करना संभव नहीं हो पाएगा, पर बाकी एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ेगी। चाहे वफ़ा बोर्ड का कानून हो, समान नागरिक संहिता का

प्रस्ताव या जनगणना के जरिए डीलिटिमिटेशन, सभी दिशाओं में भाजपा तेजी से आगे बढ़ेगी। विरोध के स्वर को दबाने की कोशिशें भी तेज होंगी- चाहे सोशल मीडिया व यू ट्यूब पर फंडा कसने का मामला हो या जनांदोलनों व जन संगठनों को ठिकाने लगाने के कानून हों या राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बदले की कार्रवाई। चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां भी अब बेलगाम तरीके से बढ़ेंगी। पिछले कुछ महीनों में सेबों अध्यक्ष और गौतम अडानी को लेकर जिन सवालों पर सरकार घिरती नजर आ रही थी, अब उन्हें दरकिनार किया जाएगा। अगले एक साल तक सत्तारूढ़ दल अपने हर निर्णय के लिए लोकप्रियता की दुहाई देगा। एनडीए में भाजपा का वजन बढ़ेगा और भाजपा में फिर मोदी जी का। ऐसे में संवैधानिक लोकतंत्र और भारत की आत्मा के लिए प्रतिबद्ध जन औदोलनों, जन संगठनों और नागरिकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। विपक्षी पार्टियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे संसद में सत्तारूढ़ पक्ष के गैर लोकतांत्रिक एजेंडे का विरोध करें, पर ऐसा नहीं लगता कि उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। विपक्ष अगर दिल्ली और बिहार के चुनाव में भाजपा को रोक सका, तो यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। आने वाले समय में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का असली मैदान संसद से ज्यादा सड़क होगा।



Negotiate with China, but warily

THE wheel seems to be turning full circle, going by the recent interaction between India's National Security Adviser (NSA) Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi. The 3,488-km-long Line of Actual Control (LAC) between the two countries has been subjected to frequent turbulence since India became independent in 1947 and the Chinese Communist Party wrested power in China in 1949. While India extended a friendly hand by supporting the inclusion of China as a permanent member of the Security Council and recognising Chinese suzerainty over Tibet, China responded by attacking India in 1962 and occupying Aksai Chin in Ladakh as well as some areas in Arunachal Pradesh.

Since then, China has frequently indulged in expansionism in Ladakh and Arunachal by violating the LAC. However, having experienced the Chinese perfidy, India realised that the only way to respond to the Chinese moves was to maintain a firm and active stance. Thus, Chinese aggression at Nathu La in 1967 and Sumdorong Chu in 1987 was forcefully opposed, resulting in the maintenance of the status quo. It became clear that the Chinese respected strength, following Deng Xiaoping's maxim of "hide your capabilities, bide your time", the Chinese maintained a low profile for the next two decades while building up their economic and military might. During this period, a series of agreements between India and China were signed — in 1993, 1996, 2005 and 2013 — to ensure peace and tranquillity and recognise existing realities along the LAC.

However, as it grew stronger, the display of China's expansionist tendencies started becoming obvious, with frequent violation of the aforesaid agreements. Thus, in 2014, the Chinese occupied Y-Junction and debarred the entry of Indian patrols to the Depsang Bulge, thereby denying approximately 1,100 sq km area for patrolling up to the Indian claim line. Likewise, Charding La access to Indian patrols near Chumar in Ladakh was denied from 2017 onwards. Additionally, a serious attempt to capture the Doklam Plateau in Bhutan was made in 2017, with the likely aim of posing a threat to the sensitive Siliguri corridor of India. The PLA design of aggressively creeping to occupy/threaten India-claimed areas emerged clearly. Then, in 2020, amid the Covid-19 pandemic, China occupied territory north of Pangong Tso, Hot Springs and Galwan in Ladakh. The Indian Army retaliated strongly at Galwan, inflicting an undisclosed number of casualties on the PLA while suffering the loss of 20 personnel itself. Additionally, it also occupied its claimed areas on the Kailash Range. The resolute stand by the Indian forces put an effective spanner in the Chinese expansionist designs. Negotiations after the hostilities ensured partial restoration of the status quo ante in most of these areas. Since then, for the past four-and-a-half years, both sides have been in an eyeball-to-eyeball confrontation in the area, with more than 50,000 troops deployed on either side. Till the boundary question between the two nations is finally settled, any future dialogue must take into account lessons from the past. Trust has been the first casualty in this relationship. Time and again, China has gone back on previously concluded agreements. In an effort to increase territorial gains, it has blatantly disregarded principles agreed upon between the two. As its power has grown vis-à-vis India's, its stance has undergone changes to exploit its strengths. A similar tendency is also visible in its interactions with littoral states of the South China Sea. This lack of trust fuels unpredictability, making contending parties wary of each other.

The collusive relationship between China and Pakistan is well known. A close nexus has developed between the two over the past 50 years. Since both harbour an adversarial stance towards India, the possibility of a two-front threat to India cannot be ruled out. Therefore, the need to tread carefully in interacting and developing ties with either can hardly be overemphasised.

State-specific agri policy is the way forward

The draft policy lacks understanding of the agrarian crisis. It has not taken into consideration the bitter experiences of farmers with private companies.

THE Indian economy seems to be on a slow downswing — 2024-25 is heading for 6.4 per cent growth against the earlier estimate of 7 per cent. The following financial year is expected to maintain the same trajectory, say a range of global analysts. The economy is clearly on a downward shift. Even on this lower gear, the economy will be moving at a faster pace than most of the other large countries. So, this slowdown is not worrying the leadership as this will still allow the system to function at a stable state. But finding the reason for the slowdown and its remedy is important as large sections of the people continue to remain very poor. What is worse is that there is a sharp difference in incomes, with only a small section enjoying the fruits of the country's high economy.

In 2022-23, the top one per cent of the population received 22.6 per cent of India's national income. Plus, there is a rural-urban divide. The per capita consumption expenditure in rural India was Rs 3,773 as compared to Rs 6,459 in urban India. Thus, it is the urban consumption that is doing the heavy lifting. The key reason for the slowdown is the inadequate consumption. This is particularly so for the urban middle class, which is the key mover for the overall demand. This will result in slack for consumption-producing businesses. These will cease to go ahead at full steam. As a result, the firms will hire fewer workers. This will slacken demand and heighten the slowdown in overall consumption. In rural India, the situation is, if anything, worse. To make ends meet, women in rural households are going out to work to help feed the families by supplementing the men's inadequate wages. But, critically, the women are working in fields, not in factories. So, they are missing out on the higher wages that factory workers earn. The high growth rate has been enabled by two forces — growing manufacturing and services. But the robust manufacturing is now slacking, as mentioned earlier. Broad-based growth would have taken place if the women in rural areas moved to factories instead of staying in farms. The high growth has also been enabled by a sharp rise in capital investment in more factories and public infrastructure, the latter made possible through higher public investment. Better roads, power and railways caused factories to feel optimistic and grow more. This caused cars, trucks and two-wheelers to face booming markets. Hence, it resulted in consumption expenditure by the middle class, particularly in urban areas. Today, these factories, mostly producing fast-moving consumption goods, are slacking. So, the dream that we have been waiting for — more jobs in factories in urban areas for more women from the rural areas — has paled. Now, let us look at services, which has been highly robust through the period of high growth. The robust consumption has caused more jobs to be created to service cars, two-wheelers, TV sets etc. As manufacturing slackens, the high growth in services is



also likely to see a slowdown. That leaves us the export services, which are made possible by the software engineers who are going up to the higher level of artificial intelligence. Here also, a negative impact is coming to the fore — nearshoring. Developed economies are becoming stricter with immigration so that there is a growing need for leading Indian software companies to go in for nearshoring. They are seeking to people development centres in the developed countries themselves with more local talent. The bright sign is that large companies of developed countries are setting up more and more highly sophisticated global development centres in India, which is creating more high-level engineering jobs.

This is good news for highly skilled Indians, but the total numbers are small. The service exports by these companies and the country are real, but the total impact on national growth is minimal. In response to the slackening growth and the exigencies of the elections, the government has decided to pay cash grants to women. This will be positive for the gender economy and demand push for consumption, but this is not a lasting economic solution. The right way to begin is to reform agriculture. This will raise agricultural productivity and raise farm incomes. This will raise rural consumption and do the economy good. But this will lead to fewer

farmhands through greater mechanisation and also better seeds and agricultural practices. The farmhands will have to be found jobs in urban areas through factories, construction and urban services by being used by municipalities to deploy services like handling of urban dry waste. But the key issue is how factories will find the need to grow capacity and set up new factories. So, the great need is to grow demand by persuading the Reserve Bank of India to lower interest rates and increase the money supply. The obvious risk will be a spurt in the inflationary level. Right now, the hope is that the rabi crop will deliver the goods, unlike the kharif crop which has been a partial letdown. The growing money supply will create higher demand for factories, which will hopefully expand their machineries and set up new plants. This will create higher demand for capital goods. The government, with its fiscal slight opening up, will create more supply for higher demand for capital goods, creating more roads, bridges and a better functioning railways. There is a need to give economic growth a push so that at the end of the day, higher demand will reduce poverty and increase the numbers of the middle class. But there is a catch in this whole scenario. If the climate lets us down, leading to droughts, floods and untimely rain damaging growing crops, it will all come to naught.

Student visa fraud

Canada needs to get its act together

AN ongoing investigation by the Enforcement Directorate (ED) has found that over 260 Canadian colleges and universities allegedly entered into agreements with two Indian firms involved in a human trafficking racket. This revelation is a major embarrassment to the Canadian government, which asserted earlier this week that it was committed to strengthening the integrity of its immigration system. It's apparent that Canada's efforts to curb visa fraud have left a lot to be desired. Canadian immigration authorities have detected thousands of potentially fraudulent student acceptance letters this year, but this is a belated step to cover up regulatory lapses. The ED, which is probing a money laundering case linked to the trafficking of Indians, has unearthed a conspiracy under which applicants were charged Rs 55-60 lakh each to facilitate their illegal entry into the US. The modus operandi was simple: take admission in a Canadian college or university; obtain a student visa;



go to Canada but don't join the institution; sneak into America through the US-Canada border. The massive fraud might have gone undetected had a horrifying tragedy not happened. A family of four from Gujarat was found frozen to death near the border in January 2022. The desperate pursuit of the American Dream had claimed the lives of Jagdish Patel, his wife and two kids.

Canada continues to be a popular destination for Indian students, genuine or otherwise, even though Delhi-Ottawa relations have soured over the past year or so. In the current year, over four lakh Indians are studying in the Maple Country. The ED findings should prompt Canada to clean up its immigration system on priority. Considering that foreign students and immigrants have played a key role in the country's economic success, Canada should crack down on shady institutions and unscrupulous agents. Closer coordination with India is a must to weed out fraudsters.

Multipronged strategy a must to curb gender-based violence

It's high time the UN General Assembly started negotiations for a global convention on the elimination of gender-based violence.

CELEBRATED Mexican activist Norma Andrade was at the UN Office in Geneva on December 5 to raise awareness about femicide. She knew exactly what it means since her daughter, Lilia Alejandra, was murdered in that city in 2001. "A woman is just disposable," Andrade said. Her pithy comment reflects the reality of the new global scourge — femicide — that has afflicted societies around the world.

An estimated 2,526 women were murdered and hundreds disappeared in Mexico's Ciudad Juarez from 1993 to 2023. In many societies, an absence of community rootedness dehumanises people, who tacitly accept femicide as the new normal. Moreover, laxity in policing, the collapse of governance structures, the complicated maze of the justice delivery system and a lack of sensitivity lead to impunity for the perpetrators.

The term 'femicide' is used to refer to all types of gender-related killings of women and girls (also known as 'femicide/feminicide'). Cases are monitored by the UN Office on Drugs and Crimes (UNODC) and UN Women. Home has become the "most dangerous place for women and girls". As per the 2024 UNODC report, as compared to 11.8 per cent killings of men, 60.2 per cent women were killed by their close partners or other family members. The UNODC report says that about 51,100 women and girls were killed in 2023 at home by their partners or other family members (48,800 in 2022) out of the total 85,000 killings of females (89,000 in 2022). Thus, femicides account for 60 per cent of all female killings globally. In other words, an average of 140 women and girls worldwide lose their lives every day at the hands of their partner or a close relative.

Gender-based violence remains a global challenge. Gender-related killings of women are "most brutal and extreme manifestation of violence against women and

girls", UN Women said on November 25, 2024. Femicide differs from other forms of homicides since there is an explicit intention to kill a female solely on the basis of her gender. In order to eliminate the root cause of femicide, the regulatory processes could trace the genesis and symptoms at home, at workplaces, schools or public spaces, including intimate partner violence, sexual harassment and other forms of sexual violence, harmful practices and trafficking. Femicide transcends borders, socio-economic status and cultures. Its severity varies from region to region and country to country. Africa had the highest toll (21,700) of family-related killings of women in 2023, followed by Asia (18,500), Americas (8,300), Europe (2,300) and Oceania (300). In Europe and Americas, 64 per cent and 58 per cent of the victims were killed, respectively, by their close partners. Women in Africa and Asia are more likely to be killed by family members than by their partners. It calls for an end to the culture of impunity and holding the perpetrators accountable amidst challenges of non-reporting of killings and the collapse of the justice delivery mechanisms in fractured societies.

There have been organised efforts as well as framing of instruments and structures to emphasise that "a woman is as much human as a man". In the post-UN Charter (1945) era, the first breakthrough came with the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the UN General Assembly (UNGA) on December 10, 1948. A feisty Indian woman delegate, Hansa Mehta, is credited with getting the word



'men' replaced by 'human beings' during the drafting process. The UDHR emphatically declares: "All human beings are born free and equal in dignity and rights" (Article 1) to provide normative equality between men and women. However, it took 30 more years to address the issue of discrimination against women when the UNGA adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) through its resolution dated December 18, 1979. In defining discrimination against women, CEDAW has identified "any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex". Still, CEDAW refrained from addressing the challenge of violence faced by women. So, it was sought to be supplemented by the UNGA through resolution 48/104 of December 20, 1993, in the

Declaration on the Elimination of Violence against Women. In defining the phrase "violence against women", the declaration brought into vogue a new global term, "any act of gender-based violence". The UNGA Declaration sought to establish an umbilical link with CEDAW. It aimed to fill the gaps in the latter.

In 1999, the UNGA designated November 25 as the International Day for the Elimination of Violence against Women. At the regional level, the only directly applicable instrument remains the 1994 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women. With 34 parties, the convention has defined violence against women as "any act or conduct based on gender that causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere". Notwithstanding the OAS (Organisation of American States) Convention, there is a rising tide of femicide in the Americas, as shown by 8,300 killings of women and girls in 2023. Femicide requires a multipronged strategy to attain the aspirational goal of 'elimination' of violence against women and girls. A 2022 book, Sexual and Gender-Based Violence in International Law, has pointed out that "the control over female sexuality remains central to the social, cultural and State-driven global normative systems". It has called for de-legitimation that can help in the elimination of femicide in the foreseeable future.

India Inc remembers Singh, his 1991 reforms

NEW DELHI. The various policies introduced by Manmohan Singh played an important role in lifting India's economic growth and making it a powerhouse, top business tycoons said while remembering the former Prime Minister and Finance Minister who passed away on Thursday at the age of 92. Aditya Birla Group chairman Kumar Mangalam Birla said Singh's most defining contribution was the 1991 reforms, which spurred a multi-decadal economic boom and more importantly reshaped the calculus of possibilities for India and Indians.

N Chandrasekaran, chairman, Tata Sons, stated that Singh was one of the stalwarts who envisioned a new, liberalised India that is taking its rightful place in the world. "Singh will always be remembered for his visionary thinking and deep insights while always being humble and upholding his personal values," added Chandrasekaran. Baba Kalyani, chairman & MD of Bharat Forge, said the Budget, the New Industrial Policy and Foreign Trade Policy that Singh announced in 1991 are pathbreaking reforms in India's economic history, that heralded the country's transformation from a command and control-based to a free-market economy and set course for India and Indian companies to participate in the globalisation era.

"While the 1991 economic reforms were his defining moment, Singh's terms as the Prime Minister will be remembered for the historic US-India Nuclear deal, setting up the UIDAI and subsequent launch of AADHAR, the MNRREGA scheme promoting rural infrastructure creation among others," said Kalyani. Singh served as the Prime Minister of India between 2004 and 2014. During this period, India saw a decade of robust economic growth, with GDP growing at an average of 6.9% annually. "Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, was a gentleman, a scholar, and a value-based politician. His leading the economic reforms, under the guidance of Sri Narasimha Rao, is what laid a strong and durable foundation for the acceleration of India's economic growth. Therefore, every Indian should be extremely grateful to this extraordinary individual for enhancing the prosperity of our country." - Narayana Murthy, founder, Infosys Limited

Delhi HC dismisses PIL challenging Patent Chief's appointment

NEW DELHI. The Delhi High Court has dismissed a public interest litigation (PIL) challenging the appointment of Unnat Pandit as the Controller General of Patents, Designs and TradeMarks.

"It is noted that the present writ petition has been filed as a Public Interest Litigation involving a service matter. In the given circumstances, we do not consider it apposite to entertain the present petition any further. The same is accordingly closed," a bench headed by Acting Chief Justice Vibhu Bakshu said in an order dated December 18. The All India Patent Officers Welfare Association (AIPOWA) had moved the court seeking quashing of Pandit's appointment on the grounds that the recommendation by a Search Committee did not comply with the "mandate of law" and that the process of appointment was arbitrary. The HC order cited guidelines of the Supreme Court that bar admitting PIL on certain categories, including "service matters and those pertaining to pension and gratuity." The petitioners had argued that Unnat Pandit's appointment was ineligible as he did not meet the requirement of a minimum of five Annual Confidential Reports (ACRs) necessary for deputation to the post of Controller General of Patents, Designs and TradeMarks.

Current account deficit narrows to \$11.2 bn in Q2: RBI

New Delhi. The country's current account deficit (CAD) moderated marginally to \$11.2 billion, or 1.2 per cent of gross domestic product (GDP), in July-September 2024 quarter from \$11.3 billion, or 1.3 per cent of GDP, in the same period of the previous fiscal. During April-September period (H1 FY2024-25), the current account deficit was \$21.4 billion (1.2 per cent of GDP) as compared with \$20.2 billion (1.2 per cent of GDP) in H1 of 2023-24, the Reserve Bank of India (RBI) data showed on Friday.

The current account deficit is the difference between exports and imports of goods and services. It is a key indicator of the country's external sector. In the second quarter of the current fiscal, merchandise



trade deficit increased to \$75.3 billion from \$64.5 billion in the same period of FY2023-24. Net services receipts rose to \$44.5 billion in Q2 FY2024-25 from \$39.9 billion a year ago. Services exports have increased on a year-on-year (y-o-y) basis across major categories such as computer services, business services, travel services and transportation services. Private transfer receipts, mainly representing remittances by Indians employed overseas, increased to \$31.9 billion in the second quarter of the current fiscal from \$28.1 billion in the year-ago period. Net foreign direct investment recorded an outflow of \$2.2 billion in the reporting quarter as compared with an outflow of \$0.8 billion in the corresponding period of 2023-24. Net inflows under foreign portfolio investment (FPI) surged to \$19.9 billion in Q2 2024-25 from US\$ 4.9 billion in Q2:2023-24. In April-September 2024, net FPI inflows stood at \$20.8 billion as compared to net inflows of \$20.7 billion a year ago.

Venture capital activity in India hits \$16.77 billion in 2024, marking 14.1% growth

NEW DELHI. Venture capital (VC) activity in India has witnessed significant growth from January to November 2024, with investments reaching \$16.77 billion across 888 deals, according to India Brand Equity Foundation (IBEF).

This marks a 14.1 per cent rise in value and a 21.8 per cent increase in deal volume compared to the same period in 2023.

The technology sector led the surge, securing \$6.50 billion—a substantial 52.5 per cent year-over-year increase. Consumer discretionary investments followed at \$2.30 billion, up 32.2 per cent, while the financial sector experienced a marginal dip to \$2.20 billion. Major deals included KiranaKart Technologies (Zepto) at \$1.3 billion and Poolside AI SAS at \$500 million.

Industry leaders are optimistic about sustained growth into 2025, forecasting more initial public offerings (IPOs) and heightened activity in late-stage funding rounds as cautious funds start deploying capital. Experts like Bhaskar Majumdar and Sajith Pai predict a positive shift in the Indian startup ecosystem, anticipating

significant easing in 2025. While concerns linger over India's economic dependence on the "India 1" segment—around 30 million households contributing heavily to GDP—confidence remains bolstered by robust savings and capital inflows. Emerging sectors like electric mobility and green hydrogen offer new opportunities, while traditional industries such as fintech and e-commerce continue to attract interest.

Additionally, intellectual property (IP)-driven ventures in deep tech areas, including robotics, drones, and semiconductor technologies, are gaining traction. The evolving global landscape, particularly the impact of the new US administration on international capital flows, is expected to present both challenges and opportunities for Indian startups in the coming year. China's venture capital (VC) funding landscape saw a significant slowdown in 2024, with a total of 2,313 deals announced between January and November, accumulating a

disclosed funding value of \$32.3 billion, according to GlobalData report. This marks a year-on-year (YoY) decline of



23.1 per cent in deal volume and a 22.5 per cent drop in funding value, as reported by GlobalData, a leading data and analytics company. In comparison, the same period in 2023 recorded 3,006 VC deals, with total disclosed funding of \$41.7 billion. The downturn reflects a challenging year for China's VC ecosystem, influenced by regulatory crackdowns, macroeconomic uncertainties, and subdued market

conditions. Aurojyoti Bose, Lead Analyst at GlobalData, stated, "VC funding activity in China has continued to remain subdued in 2024 as investor sentiments seem to have taken a hit on the back of a crackdown on companies, macroeconomic challenges, and uncertain market conditions. However, despite the decline, China remains a key player in the global VC market, second only to the US in deal volume and value."

China accounted for 15.2 per cent of the total number of VC deals announced globally during January-November 2024, with a corresponding funding value share of 13.6 per cent. Noteworthy deals in China during this period included \$1.5 billion raised by Changxin Technology, \$1.4 billion secured by AVATR, \$1.1 billion raised by IM Motors, and \$1 billion acquired by Moonshot AI.

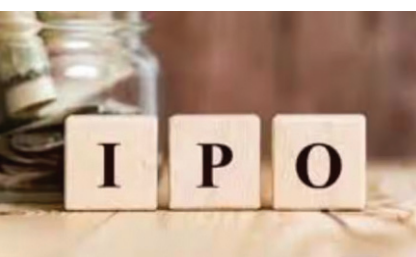
These substantial deals highlight the country's ongoing significance in the global VC landscape, even amid economic challenges.

India's IPO Market Set For Record Growth In 2025 Too: Report

New Delhi. India's IPO market achieved a historic milestone, with proceeds doubling from USD 5.5 billion in 2023 to USD 11.2 billion in 2024 says Global Data report. Murthy Grandhi, Company Profiles Analyst at GlobalData, says 2025 promises even bigger fireworks.

He said, "India's IPO market hit a bull run in 2024, with proceeds skyrocketing to USD 11.2 billion—more than doubling the USD 5.5 billion raised in 2023. The pipeline for 2025 promises even bigger fireworks, fueled by skyrocketing retail participation, hefty domestic inflows, and FPIs flexing their muscles despite being net sellers in the secondary market." He added, "This blockbuster year reflects issuer confidence and investors' insatiable appetite for listing-day pops and long-term growth plays." The government's emphasis on infrastructure and core sector development, combined with increased private capital expenditure, played a pivotal role in enhancing market dynamism. Grandhi emphasized that India's IPO boom is more than just a

numerical achievement—it signifies the evolution and resilience of the country's financial ecosystem, establishing India as a global hub for capital fundraising. India's key IPOs in 2024



included Hyundai Motor's USD 3.3 billion issue, Swiggy's USD 1.3 billion offering, NTPC Green Energy's USD 1.2 billion IPO, Vishal Mega Mart's USD 0.9 billion listing, and Bajaj Housing Finance's USD 0.8 billion issue. Other Asia-Pacific (APAC) nations also reported significant IPO activity. Japan experienced a phenomenal 275.1 per cent growth, with 69 IPOs generating USD 12.6

billion, while Malaysia recorded a 145.9 per cent increase, with 36 IPOs raising USD 1.1 billion. However, China saw a substantial decline in IPO numbers, with a 51.3 per cent drop attributed to tightened regulations.

The country had 64 IPOs, raising just over USD 5.2 billion. The region recorded 604 IPOs, raising a total of USD 33.9 billion—a 21.5 per cent increase in proceeds compared to 2023. Among APAC countries, India stood out as the top performer, with over 200 companies going public, according to Global Data, a prominent data and analytics firm.

The APAC IPO market was led by the technology and communications sector, which recorded 118 transactions worth USD 3.8 billion, followed by the financial services sector, with 60 deals amounting to USD 2.6 billion.

On the broader APAC front, standout deals included Lineage Inc's USD 4.4 billion IPO and Tokyo Metro's USD 3.2 billion listing, both in Japan. The report stated that globally too, 2025 IPO

India's CAD Likely To Exceed 2 Per Cent Of GDP In Q3 FY25 Amid Gold Import Surge: Report

New Delhi: India's Current Account Deficit (CAD) is expected to rise above 2 per cent of GDP in the third quarter of FY25, driven by a surge in gold imports, according to a report by Bank of Baroda. However, resilient services exports and remittance inflows are likely to cushion the overall impact, keeping the CAD for FY25 within a manageable range of 1.2 per cent-1.5 per cent of GDP.

India's CAD narrowed slightly to 1.2 per cent of GDP in Q2 FY25, compared to 1.3 per cent in the same period last year. Higher CAD is also because of increased trade deficit, the merchandise trade deficit widened to USD 75.3 billion in Q2 FY25 from USD 64.5 billion in Q2 FY24. The increase was largely attributed to higher non-oil imports, with gold imports rising by USD 5 billion year-on-year. In contrast, the services sector emerged as a bright spot, with net services balance increasing to USD 44.5 billion in Q2 FY25, up from USD 39.9 billion in the previous year. Software and business services exports were particularly strong, while private remittances grew to USD 29.3 billion, further supporting CAD containment. On the capital account front, India recorded a surplus of USD 11.9 billion in Q2 FY25, compared to USD 10.3 billion in Q2 FY24. The sharp rise in Foreign Portfolio Investment (FPI) inflows, which surged to USD 19.9 billion from USD 4.9 billion last year, played a key role

Non-resident Indian (NRI) deposits and External Commercial Borrowings (ECBs) also contributed positively, offsetting increased Foreign Direct Investment (FDI) outflows. Overall, the balance of payments (BoP) recorded a significant surplus of USD 18.6 billion in Q2 FY25, up from USD 2.5 billion in the same period last year, supported by robust capital inflows. The report highlighted that sluggish FPI inflows in recent months, coupled with a stronger US dollar, are likely to exert pressure on the Indian rupee. Bank of Baroda expects the rupee to trade in a range of 84-85.5/USD in the near term. The surge in November 2024's trade deficit, primarily driven by gold imports, is seen as a one-off event. However, the Bank of Baroda flagged potential risks, including the possibility of protectionist trade policies under the incoming US administration. Despite these concerns, resilient services exports and remittance inflows are expected to keep CAD levels manageable for FY25.

JSW Energy to buy O2 Power for ent value of Rs 12,468 crore

NEW DELHI. JSW Neo Energy, a wholly-owned subsidiary of JSW Energy, has announced the signing of a definitive agreement to acquire 4,696 MW renewable energy platform from O2 Power Pooling Pte. Ltd, a joint venture between EQT Infrastructure and Temasek. The transaction involves acquisition of O2 Power Midco Holdings Pte. Ltd and O2 Energy SG Pte. Ltd and is subject to approval from the Competition Commission of India and other customary regulatory clearances. The transaction values the platform at an enterprise valuation of nearly Rs 12,468 crore (\$ 1.47 bn), after adjusting for net current assets.

"This acquisition strengthens our positioning as a leading player in India's energy sector," said Sharad Mahendra, joint MD and CEO of JSW Energy. O2 Power is a renewable

energy platform with a capacity of 4,696 MW—where 2,259 MW will be operational by June 2025, 1,463 MW is currently under construction, and an additional 974 MW are in the pipeline, all scheduled for commissioning by June 2027. The platform has a blended average tariff of Rs 3.37/KWh with remaining life of 23 years. The capacities are spread across seven resource-rich states of India. This acquisition will leapfrog the company's locked-in generation capacity by 23%, from 20,012MW to 24,708MW. "This is an attractive acquisition—both from a 'Build vs Buy' trade off as well as from a quality and value perspective when compared to all acquisitions in this space over recent times, and is consistent with our long track record of being prudent in capital allocation and focusing on high cash

returns projects above our hurdle rate of mid-teen Equity IRR," said Pritesh Vinay, director (finance) and CFO of JSW Energy. ItraTech buys 8.69% stake in Star Cement. The country's largest cement manufacturer Ultratech has acquired 8.69% stake in Star Cement for ₹851 crore. Star Cement, which has a strong presence in North-Eastern India, has a production capacity of about 5.7 million tonne per annum (MTPA). The company has plans to expand its capacity to 9.7 MTPA by 2025-26 and 12 MTPA by 2027. "Some promoter and promoter group entities of Star Cement Limited, having its registered office at Village Lumshong, Dist.: East Jaintia Hills, Khasi, Meghalaya—793210 propose to sell their equity holding in Star Cement and have approached the company for the same," said Ultratech in an exchange filing on Friday.

Centre Transfers Rs 2.23 Lakh Crore For 1,206 Schemes Under Direct Benefit Transfer

In alignment with the 15th Finance Commission's recommendations, the DoE has also strengthened state finances by facilitating additional borrowing capacities, performance-linked incentives, and grants for disaster recovery, healthcare, and regional development.

New Delhi. The Finance Ministry's Department of Expenditure (DoE) has enabled the real-time, transparent distribution of funds for 1,206 schemes covered under Direct Benefit Transfer (DBT) in FY 2024-25, processing transactions worth a record Rs 2.23 lakh crore, according to a year-end report released on Friday.

"This initiative has supported the Digital India mission by extensive integrations with 117 external systems and seamless interfaces with major banks have enhanced efficiency and accountability," the review stated. The system enables the

complete tracking of funds from their release to credit into the bank account of intended beneficiaries as a result of which leakages are plugged. In alignment with the 15th Finance Commission's recommendations, the DoE has also strengthened state finances by facilitating additional borrowing capacities, performance-linked incentives, and grants for disaster recovery, healthcare, and regional development. For FY 2024-25, the net borrowing ceiling was set at Rs 9.40 lakh crore, with an additional 0.5 per cent of Gross State Domestic Product (GSDP) allocated for power sector reforms. These measures aim to boost operational efficiency and promote economic sustainability across states, the report observed. Public procurement reforms remain a key focus, with increased financial thresholds under the General Financial Rules (GFRs) and the release of a revised Procurement Manual in 2024. These updates prioritise



Ease of Doing Business, transparency, and clarity in procurement processes, ensuring alignment with modern governance requirements. The delegation of Financial Powers Rules, 2024, further simplifies decision-making by empowering departments and individuals, fostering efficiency and responsibility in financial management, the report observed. The DoE has also introduced social security reforms for

Government employees with the Unified Pension Scheme (UPS), which guarantees assured pensions and inflation-adjusted benefits for retired personnel. Scheduled for implementation from April 1, 2025, the scheme reflects the government's commitment to securing the welfare of its workforce. Simultaneously, disaster management initiatives have included the timely release of funds to states affected by floods and landslides, as well as the modernisation of fire and emergency services. These milestones are in line with the vision to maintain fiscal prudence, operational efficiency, and inclusive development. By integrating digital technologies, empowering financial autonomy, and addressing critical needs such as disaster recovery and social security, the DoE continues to strengthen governance and foster economic resilience through support for capital investment, the report added.

Charges Cut, Consumers' Power Bills To Go Down By 20% In Delhi: BJP

A statement of Delhi government said the PPAC was slashed drastically in a "new year bonanza", bringing down electricity bills for all consumers.

New Delhi. The Power Purchase Adjustment Charges (PPAC) have been sharply reduced in Delhi which will provide a relief to the city's consumers who can expect lower electricity bills now, officials said on Friday. A statement of Delhi government said the PPAC was slashed drastically in a "new year bonanza", bringing down electricity bills for all consumers. "Delhi government has been able to reduce PPAC due to honest politics and robust demand supply chain management, said Chief Minister Atishi who also holds power department portfolio.

Earlier, discom officials said that in September, PPAC of Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) was 37.88 per cent, BSES Yamuna Power Limited (BYPL) 37.75 per cent and BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) 35.83 per cent. The revised PPAC in December is 20.52 per cent for TPDDL, 13.63 per cent for BYPL and 18.19 per cent for BRPL, they said. "This will lead to a significant cut in the monthly electricity bills of the consumers," an official



stated. BJP's Delhi unit president Virendra Sachdeva said it was a victory of party workers as the BJP has been protesting against discoms and the AAP government for "looting" honest consumers in the name of PPAC.

He said the charges have been reduced due to the BJP's protests and an intervention of LG V K Saxena. Atishi said if BJP is so keen on taking credit it should reduce power prices in 22 states governed by them. Citing Delhi Electricity

Regulatory Commission (DERC) orders, Sachdeva told a press conference here that the "PPAC imposed by the three discoms has been reduced by more than 50 per cent, and resultantly the consumer bills will be reduced by 20-25 per cent".

The PPAC is added to the electricity bill to compensate for any increase in the cost of power during procurement due to factors like rise in fuel prices, changes in policies among others. It is calculated as a per cent of the sum of the fixed charge and energy charge (units consumed) in power bills. The PPAC is levied under the Electricity Act, Rules and APTEL orders. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) allows central gencos like NTPC, NHPC and transcos to make full recovery of their costs on a monthly basis. On the other hand, Delhi discoms are allowed PPAC on a post-facto quarterly basis with the approval of the DERC. The PPAC is recovered to ensure a timely pass through of the adjustment cost charges to the consumer as any delay further burdens the consumer with interest cost, officials said.

54-year-old ward boy dies in suspected suicide at Jamia Hamdard Hospital

NEW DELHI. A 54-year-old man died on early Friday after he reportedly jumped from the fifth floor washroom at Jamia Hamdard Hospital in south Delhi, police said. The victim has been identified as Mushtak Ali, employed in the hospital as a ward boy. According to police, on Friday at 1.21 am, police received information on the alleged suicide and reached the hospital where victim, a resident of the staff quarters at Jamia Hamdard campus, was found dead.

During the initial probe, it was revealed that Ali was admitted in the orthopedic ward of the hospital on Monday due to a fracture in his foot. "He resided here alone and his family lives in Odisha. He allegedly jumped from the fifth floor window of the washroom," a senior police officer said. This is the third suicidal death in as many days. On Thursday, one RJ committed suicide in Gurugram. A day prior to that, a man took his own life by setting himself on fire near the new Parliament building.

'Lack of clarity, evidence': Delhi HC acquits man convicted of sexual assault on minor girl

NEW DELHI. The Delhi High Court has overturned the conviction of a man serving life imprisonment for alleged rape and sexual assault of a 14-year-old girl under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and the IPC.

A bench comprising Justices Prathiba M Singh and Amit Sharma observed that the survivor's statement lacked clarity and sufficient evidence to substantiate claims of penetrative sexual assault. The bench highlighted that while the survivor used terms like "physical relations," these phrases were too vague to establish the occurrence of penetrative sexual assault under Section 3 of the POCSO Act or Section 376 of the IPC.

"Though consent would not matter if the girl is a minor under the POCSO Act, the phrase 'physical relations' alone cannot automatically imply sexual intercourse, let alone sexual assault," the high court noted. The bench further emphasised that the survivor's statement did not specifically allege sexual assault, and no supporting evidence was presented. "The leap from terms like physical relations or 'samband' to penetrative sexual assault must be proven on record through credible evidence and cannot simply be inferred," the bench remarked. The high court was hearing an appeal filed by the accused challenging his conviction by the trial court in December 2023. The case originated from a complaint filed by the minor's mother in 2017, alleging that her daughter had been lured and kidnapped by an unknown individual. During the investigation, the minor mentioned a "physical relationship" with the accused, leading to his conviction and life sentence by the trial court.

Delhi Traffic Police Issues Advisory Ahead Of Funeral Of Manmohan Singh

New Delhi. Delhi Traffic Police has issued an advisory ahead of the funeral of former Prime Minister Dr Manmohan Singh, scheduled for Saturday. The traffic advisory outlines restrictions and diversions on major routes in New Delhi, urging the public to avoid certain roads and use public transport to help ease congestion.

"The dignitaries of many of foreign country and other VIPs/VVIPs and the general public will visit Nigam Bodh Ghat on the occasion of state funeral of late Dr. Sh. Man Mohan Singh, Former PM of India on 28.12.2024," Delhi Traffic Police said in its advisory on Friday. According to the advisory, diversion points include Raja Ram Kohli Marg, Rajghat Red Light, Signature Bridge, and Yudhister Setu. Traffic restrictions, regulations, and diversion may be imposed on Ring Road (Mahatma Gandhi Marg), Nishad Raj Marg, Boulevard Road, SPM Marg, Lothian Road, and Netaji Subhash Marg from 7.00 am onwards, likely till 3.00 pm. The advisory advises people to avoid the mentioned roads and stretches, as well as the area where the procession will take place.

Commuters going to Old Delhi Railway Station, ISBT, Red Fort, Chandni Chowk, and Tis Hazari Court are advised to leave with sufficient time to accommodate possible delays on the route. It is also recommended to use public transport to reduce road congestion. Vehicles should only be parked in designated parking lots; roadside parking should be avoided as it obstructs the normal flow of traffic.

In case any unusual or unidentified object or person is noticed in suspicious circumstances, the public is urged to report it to the Police, they added. The last rites of Dr Manmohan Singh are to be performed at Nigambodh Ghat in New Delhi on Saturday afternoon. "Dr Manmohan Singh, former Prime Minister passed away at 9.51 PM on December 26, 2024 at AllMS Hospital, New Delhi.

Delhi High Court grants bail to man held over two years in Rs 7-crore cheating case

NEW DELHI. The Delhi High Court recently granted bail to a man held in custody for over two years in a high-profile cheating case. Justice Amit Mahajan ruled that prolonged incarceration without trial violated Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. The accused, Sandeep Tilwani, was arrested in 2022 for allegedly cheating a company of Rs 7 crore by issuing fake payment receipts for bulk rice container orders.

Despite the severity of the allegations, the court emphasised that the principles of justice demand a fair balance between the rights of the accused and the requirements of the criminal justice system.

The court observed that charges in the case had yet to be framed, and the prosecution had repeatedly delayed proceedings, seeking adjournments to file a supplementary chargesheet. Tilwani's last bail plea had been dismissed over a year ago, and the lack of progress in the trial led the court to express concern over the extended delay.

"The applicant has spent more than two years in custody. There is no likelihood of the trial being completed in the near future. In such circumstances, incarceration of the applicant for an endless period on account of non-examination of witnesses falls foul of Article 21 of the Constitution of India," Justice Mahajan stated in his December 24 order. Tilwani was granted bail on a personal bond of Rs 50 lakh and two sureties of the same amount. To address concerns of flight risk, the court permitted the prosecution to issue a Look Out Circular against him. "The law prefers bail over jail," the court noted, highlighting that while the charges were serious, the indefinite detention of the accused undermined the principles of justice. The purpose of custody, it added, was to ensure the accused's presence during the trial, which could be achieved through appropriate conditions rather than prolonged imprisonment.

Delhi Police's Economic Offences Wing accused Tilwani of making 74 bookings for 640 rice containers, valued at Rs 11.2 crore. It was alleged that he issued fake payment receipts after placing the bulk orders, causing a loss of Rs 7 crore to the complainant company. Represented by advocate Utkarsh Singh, Tilwani argued that he was framed and that the complainant filed the FIR due to financial losses.

KT Rama Rao summoned by ED in Formula-E race case on January 7

A case has been filed by probe agency ED against BRS leader KT Rama Rao and two others over alleged irregularities to the tune of Rs 55 crore in hosting the Formula-E race in Hyderabad in February 2023.

NEW DELHI. The Enforcement Directorate has issued summons to BRS working president and former minister KT Rama Rao (KTR), senior IAS officer Arvind Kumar and former Hyderabad Metropolitan Development Authority (HMDA) chief engineer BLN Reddy, in connection with the alleged financial irregularities of Rs 55 crore in hosting the Formula-E race in February 2023. KTR has been asked to appear on January 7, while Kumar and Reddy are scheduled to appear on January 2 and 3 respectively. The summons came after the central probe agency filed a money laundering case against KTR and two others in connection with the case.

An Enforcement Case Information Report (ECIR) was registered under various sections of the Prevention of Money Laundering Act, taking



cognisance of a Telangana Police Anti-corruption Bureau (ACB) FIR filed on Thursday, according to sources. The accused in the ED case are the same as those mentioned in the ACB FIR. BRS leader and party working President KT Rama Rao, the son of former Telangana chief minister K Chandrashekhara Rao, has been named as accused no. 1 followed by senior IAS officer Arvind Kumar and retired

bureaucrat BLN Reddy as accused no 2 and 3 respectively in the ACB complaint.

The probe against 48-year-old Rama Rao, popularly known as KTR, pertains to alleged payments of about Rs 55 crore, some of it in foreign currency without approval, to conduct a Formula-E race in Hyderabad during the previous regime in February last year. He denied any wrongdoing, saying "Where is the corruption in this? We have paid Rs 55 crore. They (Formula-E) acknowledged the payment". He added that it was a "straightforward" account.

"The HMDA (Hyderabad Metropolitan Development Authority) has an account in the Indian Overseas Bank and money has been transferred from that account..." KTR had said reacting to the ACB case.

Delhi Pollution Curbs Eased To GRAP 2: What's Allowed, What's Not

Delhi Air Quality: Delhi's air pollution levels showed a declining trend and the 24-hour average air quality index (AQI) stood at 324 at 7 pm on Friday.

New Delhi. As Delhi gets respite from toxic air with improved air quality due to continuous rains, Centre's panel on Delhi-NCR's air quality on Friday lifted stringent pollution curbs under stage 3 of GRAP in the national capital and surrounding areas with immediate effect. However, pollution restrictions under stage 2 of GRAP are in place in the national capital region.

Delhi's air pollution levels showed a declining trend and the 24-hour average air quality index (AQI) stood at 324 at 7 pm on Friday. According to forecasts from the India Meteorological Department and the Indian Institute of Tropical Meteorology, the air quality situation is predicted to improve further owing to favourable meteorological conditions. The Commission for Air Quality Management, responsible for strategizing air pollution mitigation in Delhi-NCR, said curbs



prescribed under stage 1 and 2 will remain in force in the region.

So, what does it mean?

Under stage 2 of GRAP, measures such as mechanised sweeping of roads, use of anti-smog guns, and sprinkling water daily will be taken to tackle dust with focused attention on identified air pollution hotspots. Power suppliers need to ensure uninterrupted supply so that the use of diesel

generator sets can be minimised. Alerts will be issued through newspapers, television, and radio to advise people about air pollution levels. Further, to ensure that the air quality index in Delhi NCR doesn't slip into 'very poor' or 'severe' category again, people are advised to use public transport and ditch personal vehicles whenever possible. People are also requested to take a less congested route to their destination even if it is slightly longer along with regularly replacing air filters in their automobiles at recommended intervals.

What's not allowed

Ban on the use of coal and firewood will still be in place in Delhi NCR, including the use of tandoors at restaurants and hotels. Use of diesel generators sets will also not be allowed except for emergency and essential services under GRAP 2.

India bids farewell to Manmohan Singh, last rites conducted with state honours

New Delhi. Former Prime Minister Manmohan Singh's last rites were conducted with full state honours at Delhi's Nigambodh Ghat on Saturday morning after top leaders from across party lines flocked to pay their last respects to the architect of India's economic liberalisation. Prime Minister Narendra Modi led the tributes, followed by top BJP leaders like Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh and JP Nadda. President Droupadi Murmu and Congress chief Mallikarjun Kharge offered floral tributes. Foreign dignitaries like the King of Bhutan Jigme Wangchuk and the foreign minister of Mauritius were also present.

Earlier in the day, Singh's final journey began from the Congress headquarters, where party leaders gathered to pay tribute. A flower-adorned vehicle carried the two-time PM's body in a solemn procession as supporters chanted "Manmohan Singh amar rahe (Manmohan Singh lives

forever)". Hundreds of Congress workers, leaders, and supporters walked alongside the procession as it wended through the national capital. Senior Congress leader Rahul Gandhi accompanied Singh's family on the way.

Meanwhile, the Centre agreed to allocate space for a memorial of the former Prime Minister after a war of words broke out between the BJP and the Congress.

Party chief Mallikarjun Kharge had written to the Prime Minister and Home Minister, requesting that Singh's last rites be performed at a place where a memorial could be built for him. Manmohan Singh's body arrived at the Congress headquarters on Saturday, giving the public and Congress workers a final opportunity to pay their tributes before the procession begins. His funeral is expected to be held at Nigambodh Ghat crematorium at 11.45 am, according to sources.



Immediately after the Cabinet meeting on Friday, Home Minister Amit Shah communicated to Mallikarjun Kharge and the family of late former Prime Minister Manmohan Singh that the Government would allocate space for the memorial, according to a statement. It further said that cremation and other formalities could happen because a trust had to be formed and space had to be allocated to it.

Authorities have issued a traffic advisory in view of the former Prime Minister's state funeral. Diversions are set at Raja Ram Kohli Marg, Rajghat Red Light,

Signature Bridge, and Yudhister Setu, with heavy traffic expected in these areas.

Restrictions will be in place on roads including the Ring Road (Mahatma Gandhi Marg), Nishad Raj Marg, Boulevard Road, SPM Marg, Lothian Road, and Netaji Subhash Marg from 7 a.m. to 3 p.m. The Centre has declared a seven-day national mourning period until January 1, during which the national flag will be flown at half-mast across the country. The national flag will also be flown at half-mast at all Indian missions and high commissions. A half-day holiday will also be declared in all central government offices and Central Public Sector Undertakings on Saturday. Besides the central government, several states, including Haryana, Punjab, Manipur, Rajasthan, Bihar, and Assam, have declared official mourning to honour the former Prime Minister.

NEWS BOX

Prince William Says He Once Gave Kate Middleton A Gift She's Never Let Him Forget

World. Prince William has shared the details of a gift he once gave Princess Kate early in their relationship - one that has since become a source of playful teasing. Prince William and Kate Middleton, both 42, met in 2001 at the University of St Andrews in Scotland.

"I did get my wife a pair of binoculars once. She's never let me forget that," the Prince of Wales revealed during an appearance on BBC Radio Five Live.

"That was early on in the courtship - I think that sealed the deal. It didn't go well. Honestly, I have no idea why I bought her a pair of binoculars, it seemed like a good idea at the time," he added. While the binoculars didn't quite hit the mark as a romantic gift, they have since become a humorous memory for the royal couple. It seems that light-hearted gifts have become a tradition within the royal family, particularly during Christmas. William's younger brother, Prince Harry, in his 2023 memoir *Spare*, had also shared that Princess Margaret, the sister of Queen Elizabeth II, once gave him a quirky fish-shaped ballpoint pen.

The royals are known for exchanging amusing presents, with Prince Harry having previously gifted Queen Elizabeth II a cheeky shower cap emblazoned with the words, "Ain't life a b-h." Meanwhile, Kate is said to have once given Harry a "grow-your-own-girlfriend" kit. This year, the royal family continued its festive traditions at Sandringham Estate in Norfolk, where they celebrated Christmas. Prince William, in preparation for the event, disclosed he was expecting to welcome 45 guests to the estate, expecting a lively gathering. Among those joining King Charles III and Queen Camilla for the holiday celebrations were William and Kate's children - Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis.

This holiday season is expected to be particularly meaningful for the family as they reunite after a challenging year. King Charles III continues his cancer treatment, while Princess Kate shared in September that she had completed her preventive chemotherapy. Prince Harry, his wife Meghan Markle, and their children - Prince Archie and Princess Lilibet - were reportedly not invited to join the royal festivities at Sandringham.

Bodycam Footage Shows New York Prisoner Beaten By Officers Before Death

Washington. Observing the US is subsidising its two neighbours Canada and Mexico to the tune of USD 100 billion and USD 300 billion, respectively, incoming US President Donald Trump on Sunday said that if that is the case then these two countries better be a part of America. Trump, 78, has threatened to impose hefty tariffs on both Canada and Mexico if they don't stop the flow of illegal immigrants into the US through their territories. "We're subsidising Canada to the tune of over USD 100 billion a year. We're subsidising Mexico for almost USD 300 billion. We shouldn't be subsidising. Why are we subsidising these countries? If we're going to subsidise them, let them become a state (of the US)," Trump told NBC News in an interview, his first on a Sunday talk show after winning the November 5 presidential elections. We're subsidising Mexico, we're subsidising Canada, and we're subsidising many countries all over the world. All I want to do is have a level, fast, but fair playing field," he asserted.

Trump refuted the observations by some American CEOs that tariffs would cost the US and increase the cost of common commodities thus putting a strain on common people. They cost Americans nothing. They made a great economy for us. They also solve another problem. If we were going to have problems having to do with wars and having to do with other things, tariffs, I have stopped wars with tariffs by saying, you guys want to fight, it's great, but both of you are going to pay tariffs to the United States at 100 per cent. They have many purposes (for), tariffs if properly used. I don't say you use them like a madman. I say properly used," he said.

"But it didn't cost this country anything. It made this country money. We never really got the chance to go all out because we had to fight COVID in the last part. We did it very successfully. When I handed it over to Biden, the stock market was higher than it was just previous to COVID coming in. It was higher. Tariffs, if properly used, are a very powerful tool, not only economically, but also for getting other things outside of economics," he said.

NYPD releases new photos of suspected killer of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson

World. A bodycam footage released on Friday shows the correctional officers at a New York prison facility beating a handcuffed inmate, who died the following day. Robert Brooks, 43, was declared dead at a hospital on December 10, a day after the incident at the Marcy Correctional Facility in New York. New York Attorney General Letitia James, who is currently investigating the case, made the December 9 body camera footage public on Friday. After an internal review, New York Governor Kathy Hochul ordered the firing of 13 officers and a prison nurse for their alleged involvement in the assault, BBC reported. Hochul noted she was "outraged and horrified" by the videos of Brooks' "senseless killing." Letitia James' office has opened an investigation, while the union representing state prison workers has termed the footage as "incomprehensible." In the footage, the officers hit Brooks in the face and groin; the handcuffed prisoner sat on a medical examination table. At one point, an officer used a shoe to strike Brooks in the stomach, another one lifted him by his neck and dropped him back on the table. Soon after, they removed his shirt and pants, and he was left motionless on his back. The viral videos, which do not have any audio since the body

Ukrainian troops struggle to hold kursk as russian counteroffensive intensifies

KYIV. Five months after their shock offensive into Russia, Ukrainian troops are bloodied and demoralized by the rising risk of defeat in Kursk, a region some want to hold at all costs, while others question the value of having ventured in at all.

Battles are so intense that some Ukrainian commanders can't evacuate the dead. Communication lags, poorly timed tactics have cost lives, and troops have little way to counterattack, according to seven front-line soldiers and commanders who spoke to The Associated Press on the condition of anonymity to discuss sensitive operations. Since being caught unaware by the lightning Ukrainian incursion, Russia has amassed more than 50,000 troops in the region, including some from its ally North Korea. Precise numbers are hard to obtain, but Moscow's counterattack has killed and wounded thousands, and the overstretched Ukrainians have lost more than 40% of the 984 square kilometers (380 square miles) of Kursk they seized in August.

Russia's full-scale invasion three years ago

left it holding a fifth of Ukraine, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has hinted that controlling Kursk could help force Moscow to negotiate an end to the war. However, five Ukrainian and Western officials in Kyiv, who spoke on condition of anonymity to discuss sensitive military matters, fear that gambling on Kursk will weaken the entire 1,000-kilometer (621-mile) front line, and Ukraine is losing precious ground in the east. "We have, as they say, hit a hornet's nest. We have stirred up another hot spot," said Stepan Lutsiv, a major in the 95th Airborne Assault Brigade. The Border Raid that became an Occupation Army chief Oleksandr Syrskyi has said that Ukraine launched the operation because officials believed Russia was about to launch a new attack on northeast Ukraine.

The operation began on August 5 with an order to leave Ukraine's Sumy region for what they thought would be a nine-day raid to stun the enemy. It turned into an occupation that Ukrainians welcomed as



their smaller country gained leverage and embarrassed Russian President Vladimir Putin. Gathering his men, one company commander told them: "We're making history; the whole world will know about us because this hasn't been done since World War II."

Privately, he was less certain.

"It seemed crazy," he said. "I didn't understand why." Shocked by the success, largely because the Russians were caught by surprise, the Ukrainians were ordered to

advance beyond the original mission to the town of Korenevo, 25 kilometers (16 miles) into Russia. That was one of the first places where Russian troops counterattacked. By early November, the Russians began regaining territory rapidly. Once in awe of what they had accomplished, the troops' opinions are shifting as they come to terms with losses. The company commander said half of his troops are dead or wounded. Some front-line commanders said conditions are tough, morale is low, and troops are questioning command decisions even the very purpose of occupying Kursk. Another commander said that some orders his men have received don't reflect reality due to communication delays. Delays occur especially when territory is lost to Russian troops, he said. "They don't understand where our side is, where the enemy is, what's under our control, and what isn't," he said. "They don't understand the operational situation, so we act on our own discretion."

True Statesman, Kind, Dedicated Public Servant: Biden Pays Tribute To Dr Manmohan Singh

Washington. US President Joe Biden on Saturday paid heartfelt tributes to former Prime Minister Dr Manmohan Singh, describing him as a "true statesman," a "kind and humble person," and a "dedicated public servant." Dr Singh, who served as India's 14th Prime Minister and was widely regarded as one of the nation's most distinguished economists, passed away on Thursday night at the age of 92 at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in New Delhi. Acknowledged as the 'Architect of India's economic reforms,' Dr Singh led the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) government as Prime Minister for two consecutive terms from 2004 to 2014, leaving a lasting legacy on India's economic and diplomatic landscape. In an official statement issued by the White House, President Biden said, "Jill and I join the people of India in grieving the loss of former Indian Prime Minister Manmohan Singh."

He emphasized that "the unprecedented level of cooperation between the United States and India today would



not have been possible without the Prime Minister's strategic vision and political courage." President Biden credited Dr Singh for key milestones in Indo-US relations, including the landmark US-India Civil Nuclear Agreement and the establishment of the Quad between Indo-Pacific partners. He added that Dr Singh charted pathbreaking progress that will continue to strengthen our nations and the world for generations to come.

"He was a true statesman. A dedicated public servant. And above all, he was a kind and humble person," Biden stated.

Recalling his personal interactions with Dr Singh, Biden mentioned their meetings during his tenure as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee in 2008 and as Vice President during Dr Singh's official visit to the United States in 2009. "He also graciously hosted me in New Delhi in 2013," Biden said, noting their shared belief in the US-India relationship as one of the most consequential in the world.

Expressing his condolences, Biden added, "During this difficult time, we recommit to this vision to which Prime Minister Singh dedicated his life. Jill and I send our deepest condolences to former First Lady Gursharan Kaur, their three children, and all the people of India." Earlier on Friday, US Secretary of State Antony Blinken had also expressed his sorrow, calling Dr Singh "one of the greatest champions of the US-India strategic partnership." Blinken highlighted Dr Singh's pivotal role in advancing the US-India Civil Nuclear Cooperation Agreement and his contribution to India's rapid economic growth.

Israeli airstrikes hit Yemen airport as passenger plane lands, UN official reports

World The United Nations has condemned Israeli airstrikes on Yemen's Sanaa airport, which struck as a civilian Airbus 320 with hundreds of passengers was landing and a UN delegation was preparing to leave. Speaking on Friday, Julien Harnais, the UN's top humanitarian official in Yemen, described the incident as "a terrifying experience", as reported by Associated Press (AP). Harnais said the airstrikes on Thursday destroyed the airport's control tower while a Yemenia Airways plane was taxiing. "Thankfully, the plane landed safely, and passengers disembarked. But it could have been much worse," he said, addressing reporters in a video conference from Sanaa. Two airstrikes hit approximately 300 metres south and north of the VIP lounge, where Harnais and 15 others, including WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, were waiting. "We had no warning of any potential airstrikes, and daytime bombings in Sanaa are extremely rare," Harnais said. The strikes killed at least three people and injured dozens, including a UN

Humanitarian Air Service crew member, who suffered severe leg injuries from shrapnel. The injured man was rushed to a Sanaa hospital for surgery before being flown to Jordan. UN security officials evacuated the delegation to armoured vehicles,



where they waited for 40 minutes before moving to safety. Harnais noted that the delegation spent the night at a UN compound, and the following day, the UN team, including the injured crew member, departed for Jordan on a flight without an operating control tower. Israel's military stated it was unaware of the UN delegation's

presence at the airport. The strikes, they claimed, targeted facilities used by Houthi rebels and Iran. Harnais refuted this, saying, "Sanaa airport is a civilian facility used by the UN and for humanitarian flights, including one vital Yemenia flight to and from Amman", reported by AP. Yemen, embroiled in a decade-long civil war, has seen Houthi rebels escalate attacks on Israel following the October 7 assault by Hamas. The Houthis have targeted ships in the Red Sea and launched drones and missiles at Israel, prompting intensified Israeli military responses. Israeli strikes have also damaged Yemen's key port of Hodeidah, critical for importing 80% of the nation's food and over 90% of its medical supplies. Harnais reported that an earlier strike destroyed tugboats, and is estimated to have reduced the harbor's capacity by 50%, the UN official said, while damage from Thursday's airstrikes hasn't been assessed yet.



over the past four years and agreed that cooperation has strengthened in many sectors. Jaishankar expressed confidence that ties between India and US will serve mutual interests and global good. Jaishankar, during his visit, met India's Ambassador to US, Vinay Kwatra and Consul Generals based in New York, Chicago, San Francisco, Seattle, Houston and Atlanta. The officials discussed opportunities for deepening India-US partnership, focusing on technology, trade and investments. The visit by the External Affairs Minister comes after Prime Minister Narendra Modi visited the US earlier in September and participated in the fourth Quad Leaders' Summit in Wilmington, Delaware. The US and India have seen frequent high-level interactions. Earlier on Tuesday, senior diplomats from India and the United States, including Deputy Secretary of State Richard Verma, highlighted the strengthening of bilateral ties between the two countries. India-US bilateral relations have developed into a "global strategic partnership," based on shared democratic values and increasing convergence of interests on bilateral.

Was Not Sure I Could Survive": WHO Chief On Escaping Israel Strike On Yemen

Zurich. The head of the World Health Organization said on Friday he was not sure he was going to survive an air strike on Yemen's main airport carried out by Israel a day earlier during a series of attacks on the Iran-aligned Houthi movement.

Speaking after his ordeal at the Sanaa International Airport on Thursday, WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the explosions that rocked the building were so deafening that his ears were still ringing more than a day later. Tedros said it quickly became apparent the airport was under attack, describing people "running in disarray" through the site after approximately four blasts, one of them "alarmingly" close to where he was sitting near the departure lounge. "I was not sure actually I could survive because it was so close, a few meters from where we were," he told Reuters. "A slight deviation could have resulted in a direct hit." Tedros said he and his colleagues were stuck at the airport for the next hour or so as what he thought were

drones flew overhead, feeding concern they could open fire again. Among the debris, he and colleagues saw missile fragments, he said. "There (was) no shelter at all. Nothing. So you're just exposed, just waiting for anything to happen," he said.

The Israeli strikes on Yemen came after Houthis repeatedly fired drones and missiles toward Israel in what they describe as acts of solidarity with Palestinians in Gaza. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said afterwards that Israel was "just getting started" with the Houthis.

The Houthi-controlled Saba News Agency said three people died in the strikes on the airport and three were killed in Hodeidah, with 40 others wounded in the attacks.

Speaking by telephone from Jordan, where he flew on Friday, helping to evacuate a U.N. colleague seriously injured at the airport for further medical treatment, Tedros said he had received no warning Israel could be about to strike the airport.



The injured man, who worked for the UN Humanitarian Air Service, was now "OK" and in a stable condition, he said.

Tedros traveled to Yemen over Christmas to try to negotiate the release of UN staff and others held there. He acknowledged that he and colleagues knew the trip was risky in light of high tension between Israel and the Houthis. But such was the window of opportunity to work for the release of the UN personnel that they believed they had to take it, said Tedros, a former Ethiopian foreign minister. He said talks with Yemeni

authorities had gone well and that he saw a chance that the 16 UN staff as well as employees of diplomatic missions and NGO workers held there could be freed.

He declined to engage in recriminations over the attack but said his itinerary had been shared publicly and expressed surprise that civilian infrastructure should have been targeted. "So a civilian airport should be protected, whether I am in it or not," he said, before observing there was "nothing special" about what he had faced in Yemen. "One of my colleagues said we narrowly escaped death. I'm just one human being. So I feel for those who are facing the same thing every single day. But at least it allowed me to feel the way they feel." "I'm worried about our world, where it's heading," Tedros added, urging world leaders to work together to end global conflicts. "I have never... as far as I can remember, seen the world really being in such a very dangerous state."

NEWS BOX

Justin Langer picks 'gladiatorial' Virat Kohli over Sachin Tendulkar, Brian Lara

Former Australia batter Justin Langer said that Virat Kohli is the best batter that he has ever seen. Speaking ahead of Day 3 of the 4th Test match between India and Australia, Langer rated Virat Kohli ahead of Sachin Tendulkar and Brian Lara for his gladiatorial attitude and incredible fitness. Langer said Kohli would be the one player he would watch if he was given a choice between the greats of the game. Langer, who has played 105 Test matches for Australia, rated the former India captain ahead of the legendary Ricky Ponting. "You asked me Mark why I said yesterday that Virat Kohli is the best player that I have ever seen. There were a few raised eyebrows, but he actually is. We talk about Sachin, what a player. It was one of the privileges of my life to play against Sachin Tendulkar and, of course, with Ricky Ponting and Brian Lara. If I had my last rupee or my last dollar, I would pay to watch Brian Lara bat, but if I had my life and my last dollar, and both of them



together, I would have Virat Kohli batting for me," Langer said during commentary on Day 2 of the Boxing Day Test. "The reason why I say that is not because of the expansive shots, his cover drives or his hook shots. But you just saw, the way he is watching the ball, his running between the wicket, his fielding, his gladiatorial style of leadership. His elite fitness level, everything that he's brought to the table. His numbers speak for themselves. You can never argue with data. Those are the reasons, why he is the best player I have ever seen. And we have seen a lot of them. But he is the one player, I think; if I had to put my money on, he would be the one," he further said. Kohli has had a difficult time in the Boxing Day Test match so far. After a bust-up with debutant Sam Konstas, Kohli was booed by the MCG crowd. The batter looked in exceptional touch in India's first innings, but later was involved in a mega mix-up with Yashasvi Jaiswal, resulting in a run-out of the youngster.

Stupid, Stupid, Stupid: Furious Gavaskar slams Rishabh Pant for reckless dismissal

New Delhi. Furious Sunil Gavaskar slammed wicketkeeper-batter Rishabh Pant for his reckless dismissal on Day 3 of the 4th Test match at the Melbourne Cricket Ground. While commentating for the host broadcaster, Gavaskar called Pant stupid after the keeper-batter was dismissed for just 28 runs in India's first innings at the Boxing Day Test match.

With India in dire straits, Pant's decision to play an unorthodox scoop shot off Scott Boland's bowling left many fans and experts questioning his temperament and approach in high-pressure situations. Gavaskar hit out at Pant and used some harsh words for the batter after his dismissal. Pant had looked jittery from the very start of his innings on Day 3. He nearly got caught twice at the slip cordon in the first hour of play and then



survived 2 run-out attempts due to on-field mix-ups with Ravindra Jadeja. After settling down his nerves near the hour mark, Pant decided to scoop Scott Boland's full-length delivery behind the keeper. The batter did not get the ideal connection and was caught at deep third man after top-edging the ball.

"Stupid, stupid, stupid! You have two fielders there, you still go for that shot. You have missed the previous shot and look where you have been caught. You have been caught at deep third man. That is throwing away your wicket. Not in the situation that India was. You have to understand the situation as well. You cannot say that that's your natural game. I'm sorry that is not your natural game. That is a stupid shot that is letting your team down badly," Sunil Gavaskar fumed while commentating on the match. "He should not be going in that dressing room. He should be going to the other dressing room," he further added. Co-commentator Harsha Bhogle was visibly left surprised by Gavaskar's choice of words for Pant but did not attempt to stop the legendary former cricketer. After Pant's dismissal, Jadeja got out in the morning session as well.

'Stupid, Stupid, Stupid': Angry Sunil Gavaskar Slams Rishabh Pant's Reckless Dismissal Against Australia

Sunil Gavaskar slammed Rishabh Pant's 'stupid' dismissal in India's Boxing Day Test against Australia. Pant's reckless scoop shot off Scott Boland sparked criticism.

IND vs AUS. Day 3 of the fourth Test between India and Australia at the Melbourne Cricket Ground (MCG) saw former Indian cricketer Sunil Gavaskar express his frustration over Rishabh Pant's reckless dismissal. Pant, known for his aggressive style, fell for just 28 runs in India's first innings, playing an unorthodox scoop shot off Scott Boland. With India struggling to recover in the high-stakes Boxing Day Test, Pant's decision to play a risky shot left fans and experts questioning his shot selection. Gavaskar, commentating for the host broadcaster, labeled Pant's decision "stupid," criticizing his lack of awareness in a critical situation. Sunil Gavaskar On Rishabh Pant's Dismissal



"Stupid, stupid, stupid! You have two fielders there, you still go for that shot. You have missed the previous shot and look where you have been caught. That is throwing away your wicket. Not in the situation that India

was," Gavaskar said, clearly irate. He added, "You cannot say that's your natural game. That is a stupid shot that is letting your team down badly." Pant had appeared nervous from the outset of his innings. Early on, he

narrowly avoided being caught twice at slips and survived two potential run-outs due to miscommunication with Ravindra Jadeja. However, after settling in, he attempted a scoop over the keeper but ended up top-edging the ball, leading to his dismissal at deep third man.

Harsha Bhogle, Gavaskar's co-commentator, was visibly surprised by the harsh critique but refrained from intervening.

Following Pant's exit, Jadeja was also dismissed in the morning session. Despite the setbacks, India's innings found some stability through Nitish Reddy and Washington Sundar. At the time of writing, Reddy had scored a gritty half-century, steering India past 300 runs and keeping their hopes alive in the match. The incident has sparked a debate about Pant's approach in pressure situations, with many calling for greater responsibility from the talented but inconsistent wicketkeeper-batter. Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in India news and world news on Zee News.

Nitish Reddy should be batting at No 6, will help balance of Indian side: Ravi Shastri

New Delhi. Former India head coach Ravi Shastri has strongly advocated for young all-rounder Nitish Reddy to move up the batting order, stating that his MCG knock warrants a promotion to No. 6 in India's Test lineup. Shastri's remarks came after Nitish played a fearless, unbeaten 85-run knock in the post-lunch session on Day 3. The SRH all-rounder was beautifully complemented by Washington Sundar's steady 40 not out as the visitors reached 326 for seven before a light drizzle brought an early tea on the third day of the fourth Test against Australia. The two young all-rounders shared a record 105-run stand for the eighth wicket, not only avoiding the follow-on but also justifying their selection in the playing XI. Head coach Gautam Gambhir's decision to back them was validated as both Reddy and Sundar provided crucial stability in a challenging situation. "I feel that the way he's batted, this is the last time he will bat at 7. To get the balance of the side, you need him to go higher up the order, either 5 or 6 and then you have the opportunity of playing 5 bowlers to take the 20 wickets, and he's



given that kind of confidence to the selectors and the team management and the captain," Ravi Shastri said during the tea break on Day 3. Shastri highlighted that promoting Reddy would not only strengthen the batting lineup but also allow the team to field an extra bowler, a critical factor in achieving success in Test cricket. "Reddy is fully capable of batting in the top 6. Then it changes the whole balance of the game," he added. "You go to Sydney with him batting in the top 6, and you're playing five bowlers." Despite India's fightback, Australia, who scored 474

in their first innings, are still leading by 148 runs. However, the placid Melbourne track suggests that the match is likely heading for a fifth-day finish, as taking 20 wickets seems a difficult task for either side. Nitish after a string of near-misses, finally crossed the elusive fifty-run mark to the delight of his fans and teammates. The 21-year-old reached the milestone with a boundary off Mitchell Starc and celebrated with a gesture inspired by the movie Pushpa:

The Rise.

Reddy's innings came at a crucial juncture, with India under pressure after a batting collapse late on Day 2, which saw them lose three key wickets, including Yashasvi Jaiswal (82) and Virat Kohli (36). On the third day, the early dismissals of Rishabh Pant and Ravindra Jadeja further compounded the team's woes. However, Reddy and Sundar's partnership steadied the ship, helping India avoid the follow-on and reduce the deficit.

Australia name 14-member squad for Women's Ashes, Sophie Molineux misses out

New Delhi. Australia, on Saturday, named a strong 14-member squad for the Women's Ashes. Spin-bowling all-rounder Sophie Molineux has been ruled out due to a knee injury. Kate Beerworth, the Australian Women's physiotherapist, said that Molineux will undergo a surgery on her left knee, after which a call on her return will be taken. The left-arm spinner sustained an injury during the home series against India. Grace Harris will join the squad only for the three-match T20I series. Shawn Flegler, Cricket Australia's Head of Performance and National Selector, was happy with the team's recent performances against India and New Zealand. He was also delighted with Alyssa Healy's return against the White Ferns after she missed



the series against India.

"We're pleased with how the side performed in recent series against India and New Zealand and are confident we have a balanced squad capable of retaining the Ashes," Flegler said.

"It was pleasing to see Alyssa Healy return to action against New Zealand and looked in good touch, along with a number of batters continuing their strong form on from the recent series against India," Flegler said. Lauding Georgia Voll, who made her debut in the ODI series against India, the selector said, "Whilst Georgia Voll didn't play against New Zealand, she's made a brilliant start to her international career and will be a strong option with the bat if required in her debut Ashes series." The Women's Ashes starts with the ODI series on January 12, 14 and 17. It will be followed by the three-match T20I series on January 20, 23 and 25. The Day-Night Test at the Melbourne Cricket Ground starts on January 30. Australia squad for Women's Ashes: Alyssa Healy, Darcie Brown, Ashleigh Gardner, Kim Garth, Grace Harris (T20s only), Alana King, Phoebe Litchfield, Tahlia McGrath, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland.

Cristiano Ronaldo makes bold Manchester United ownership claim: It's like aquarium

New Delhi. Cristiano Ronaldo has insisted that Manchester United's problems are not due to new manager Ruben Amorim and believes he could fix them if he were the club's owner. Ronaldo has remarkably positioned himself as the person to resolve United's ongoing issues while discussing his ambition to one day become a club owner.

Amorim has lost five of his 10 games in charge of United, including four of the past five in the Premier League, and stated ahead of the next game against Newcastle United that his job is not secure. However, Ronaldo, who scored 145 goals over two spells at United and has been critical of the club's ownership in recent years, maintains that his countryman is not to blame.

"The Premier League is the most difficult league in the world," Ronaldo, now playing for Al Nassr in Saudi Arabia, said at the Globe Soccer Awards in Dubai, United Arab Emirates, on Friday. "All the teams are good, all the teams fight, all the teams run, all the



players are strong. Football is different right now. There's no easy games anymore.

"I said this one and a half years ago, and I will continue to say it: The problem is not the coaches.

Cristiano Ronaldo has defended Ruben Amorim amid the Manchester United "storm" and made a very bold claim about his possible return to the club.

"It's like an aquarium. If you have the fish inside and he's sick and you take him out and you fix the problem and you put him again in an aquarium they will be sick again.

"The problem of Manchester United is the same. The problem is not always the coach. It's much more than that. If I will be the owner of the club, I will make things clear and adjust what I think is bad there."

Magnus Carlsen disqualified from World Rapid and Blitz Chess Championship for violating dress code

Carlsen was disqualified and was not paired for Round 9 of the Rapid championship taking place at Wall Street.

NEW YORK. Five-time world champion Magnus Carlsen was first fined and then disqualified from the World Rapid and Blitz Chess Championship here for his refusal to comply with FIDE's dress code after turning up in jeans. Defending champion Magnus Carlsen was fined Dollar 200 for wearing jeans, which are explicitly prohibited under tournament rules. When Carlsen refused to change his attire immediately after being instructed by chief arbiter Alex Holowczak, he was disqualified and did not participate in Round 9 of the Rapid Championship at Wall Street. One of the game's greatest players, the Norwegian ace had agreed to follow the dress from the next day but was not ready to do it immediately, resulting in his



disqualification. In a statement, the game's global governing body FIDE emphasised that the dress code rules are well-communicated to all participants and designed to ensure professionalism.

"The dress code regulations are drafted by members of the FIDE Athletes Commission,

which is composed of professional players and experts. These rules have been in place for years and are well-known to all participants and are communicated to them ahead of each event. FIDE has also ensured that the players' accommodation is within a short walking distance from the playing venue, making adherence to the rules more

convenient." FIDE said in the statement which was posted on 'X'. The Chief Arbiter informed Mr. Carlsen of the breach, issued a USD 200 fine, and requested that he change his attire. Unfortunately, Mr. Carlsen declined, and as a result, he was not paired for round nine. This decision was made impartially and applies equally to all players.

Earlier, Russian Grandmaster Ian Nepomniachtchi was also penalised for a similar violation but he complied by changing his attire, allowing him to continue in the event. Meanwhile, "upset" with the turn of events, Carlsen said he won't participate in the Blitz section of the championship as he is "pretty tired" of FIDE's dress code policies. "I am pretty tired of FIDE, so I want no more of this. I don't want anything to do with them. I am sorry to everyone at home, maybe it's a stupid principle, but I don't think it's any fun," Carlsen told the Norwegian broadcasting channel NRK. "I said I don't want to bother changing now, but I can change until tomorrow, that's fine. But they didn't want to compromise. I've reached a point where I am pretty upset with FIDE, so I didn't want to either. Then that's how it goes," he added.

Tamannaah Bhatia

Nails Street-style Look With White Tee And Denims

Tamannaah Bhatia has proven once again that she's the reigning queen of casual chic numbers. Recently, the actress was caught by the paparazzi looking effortlessly stunning as she stepped out in the city. The video, shared on Instagram, quickly caught the attention of the fans. For this casual outing, Tamannaah kept things classic yet stylish with a simple white tee and denim combination. Her jeans in a relaxed fit with a flared hem made sure she stayed comfortable while still looking fashionable. To complete the laid-back vibe, she paired the outfit with fresh white sneakers and statement accessories. The actress embraced her natural beauty as she opted for a no-makeup look. Her shoulder-length straight hair was left loose.

As the paparazzi clicked away, Tamannaah flashed a smile before stepping into her car.

Tamannaah recently celebrated her 35th birthday on December 21 by heading to Goa for a fun getaway. She was joined by her boyfriend Vijay Varma and a group of close friends, including Randeep Hooda's wife, Lin Laishram. But before soaking in the sunny vibes of Goa, the actress had a quick trip to Lucknow for work-related commitments where she also sat down for an interview with a media portal. During the conversation, she opened up about her journey in the



entertainment industry.

Talking about her career, Tamannaah shared that her passion for performing arts was something that always came naturally to her. "It was very strong urge to do what I am doing today. While I was doing theatre and some kind of work initially, the performing arts also brought a kind of joy to me," she said.

"Even though sometimes the timings have been crazy, it never felt like work to me. Strangely, people keep asking me what I do for pleasure, but for me, work only has been my pleasure, and I never seek pleasure anywhere else," she added. On the professional front, Tamannaah was last seen in the Netflix film Sikandar Ka Muqaddar, a gripping crime drama. Directed by Neeraj Pandey, the movie follows a police officer investigating a diamond heist, uncovering twists along the way. The film also starred Avinash Tiwary, Jimmy Shergill and Rajiv Mehta in key roles. She also grabbed attention with her special appearance in the blockbuster Stree 2, starring Rajkummar Rao and Shradha Kapoor.



AR Rahman Reveals How A Drunk Guitarist's Comment On His Music Affected Him



Oscar-winner AR Rahman might be at the pinnacle of his music career but it all didn't come easy. He faced a number of hardships in his path to fame. The musician started working at a very young age to support his family. However, in a recent conversation, he revealed how a condescending comment about his music skills deeply affected him.

In a recent interview, AR Rahman recalled the time he was working with several companies and was getting influenced by them. At that initial phase of his career, a drunk guitarist questioned his music skills. He made a very condescending comment on Rahman's skills, leaving a deep impact on him. "I went through a phase where I was playing for a couple of composers, and I was in a band. This one time, when I was young, the guitarist in the band was drunk, and he turned to me and said, 'What are you playing? You are playing film music.' He made a very condescending comment about my playing. This was in 1985 or 86, I think," Rahman told O2 India.

Rahman also explained that he realised the remark's deep meaning after days. But fortunately, with a turn of events, the comment worked as an eye-opener for the musician. He said, "At the moment, I didn't realise what he meant, but weeks later, it hit me, and I realised that whatever he said was right. When I thought deeply about his remark about me, I realised that I was getting influenced by the composers I was playing for," adding how he gradually began to realise his style. "After this, I consciously began to move away from it. And my mental journey of identifying 'what will be my style' began. It took me about seven years, and I completely moved away from the influences."

In the same conversation, Rahman also mentioned how he took it as a positive influence and started working on the same. He admitted that although the guitarist didn't say anything bad to him, he moved away from it after seven years. Rahman's decision to take his career in the right direction, despite such remarks leaving a long-lasting imprint on him, proves his determination to do good work. Rahman will next compose music for Hansal Mehta's upcoming series Gandhi. Additionally, he has compositions for Ram Charan and Buchi Babu's upcoming movie, RC16, in his pipeline.

Is Kartik Aaryan Charging Rs 50 Crore For Karan Johar's Tu Meri Main Tera? Here's What We Know



This Christmas, Bollywood fans were in for a special treat as Kartik Aaryan and Karan Johar officially announced their upcoming romantic comedy Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri. The film marks a significant collaboration between the two and has already created a buzz with reports revealing that Kartik will be paid an impressive Rs 50 crore for his role. With a total budget of Rs 150 crore, the project is being touted as one of the most ambitious rom-coms in recent times.

According to Zoom, Kartik's market value has surged following the blockbuster success of Chandu Champion and Bhool Bhulaiyaa 3. The actor's rising popularity has positioned him among Bollywood's highest-paid stars, with his Rs 50 crore paycheck being a testament to his growing influence. Meanwhile, Bollywood Hungama has highlighted the scale of Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, describing it as a grand venture mounted on an impressive budget.

The official announcement video, released on December 25, 2024, gave fans a glimpse of what to expect from the film. In the clip, Kartik's character Ray humorously discusses how his three previous relationships ended badly, vowing to ensure his fourth relationship doesn't meet the same fate. The lighthearted tone of the video set the stage for what promises to be an entertaining love story. Sharing his excitement on social media, Kartik wrote, "Tumhara RAY aa raha hai RUMI. Mummy ki khaayi hui kasam, yeh Mumma's boy poori karke he rehta hai!"

Super excited to return to my fav genre Rom-com #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri... The biggest love story coming to cinemas in 2026." Directed by Sameer Vidwans, who previously worked with Kartik on Satyaprem Ki Katha, the film is being presented by Dharma Productions and Namah Pictures.

Swara Bhasker's

Filmy Twist While Teaching Daughter Raabiyaa About Birds Is Unmissable



Swara Bhasker and Fahad Ahmad are doting parents to their one-year-old daughter Raabiyaa. The Veere Di Wedding actress loves to share glimpses of her day-to-day life with her little munchkin, on Instagram. In a recent video, she is seen teaching her daughter about birds. To make things interesting, she taught her daughter about the birds in a fully filmy way, leaving fans amused. She added her own twist to the song 'Kabootar Jaa' to make it 'baby appropriate', and the video has gone viral on Instagram!

On Friday morning, Swara Bhasker took to her social media to share a reel that shows her teaching Raabiyaa about birds, by showing pictures. She first showed her a parrot, and then a dove. Next up, was a pigeon. She added a filmy twist while teaching Raabiyaa about pigeon, thereby introducing her little princess to Bollywood classics. She is seen singing the song 'Kabootar Ja,' from Salman Khan and Bhagyashree's 1989 film 'Maine Pyar Kiya.' However, she altered the

lyrics of the song slightly to make it 'age-appropriate' for Raabiyaa. "Pehle pyaar ki pehli chitti Mamma se Raabu ko de aa," she sang. The little one shook her head, and cutely grooved to the song. Both Swara and Raabiyaa served major mom-daughter goals as they wore similar white printed outfits. Check out the video below!

The text on the reel read, "When Mamma is a Bollywood buff... but has to keep it age appropriate!" Sharing the video, Swara Bhasker wrote, "Introducing Raabu to Bollywood classics- baby appropriate edition!" The actress' hubby Fahad Ahmad dropped several red heart emojis on the post. "Swara you're adorable," read one comment on her post, while another one read, "awww the little angel takes after her mumma Grooving to Bollywood alreadyyyyy she's the luckiest So much spirit and spunk, learning is always funnn!"

Swara Bhasker and Fahad Ahmad tied the knot in February 2023. They welcomed their first child, daughter Raabiyaa, in September that year.

Swara Bhasker shared a lovely video as she introduced her daughter Raabiyaa to Bollywood classics. She sang the song Kabootar Jaa, but improvised it to make it 'baby appropriate'!